• वर्ष-4
• अंक-35
रायपुर, बुधवार
18 सितंबर 2024
• पृष्ठ-8
• मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6>> बच्चों को ऐसे बढ़ाएं आगे...

पीएम आवास योजना में शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर होगी कार्रवाई: साय

मोदी के जन्मदिन पर पक्का मकान का तोहफा

रायपुर। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2044 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रान्सफर की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं अन्य मंत्रीगण की मौजूदगी में मोर आवास-मोर अधिकार कार्यक्रम राजधानी स्थित रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की हैं। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण, पूजा सामग्री प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपने साकार हो रहा हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं हैं। आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिला है। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हज़ार हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह की कोताही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया गया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ ही अपने घर एवं आस-पास के परिवेश सहित स्कूलों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिखने का दिन है। छत्तीसगढ़ के आवासहीन लोगों के जीवन में एक नई रोशनी मिलेगी। हमने जो वादा किया था, उसे आज पूरा किया है। यह सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने 4 करोड़ आवास बनाकर गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।

इसके साथ ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवासों की स्वीकृति दी गई है जिससे यह योजना और अधिक प्रभावी हो रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। सरकार बनते ही हर महीने 25 हजार नए आवास बनकर तैयार हो रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव की तैयारी पूरी

आज 24 सीटों पर डाले जाएंगे वोट

चरण 1 में मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएच पोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू विधानसभा, कोकेरनाग (एसटी), अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्रीगुफवारा-बिजबेहरा, शंगस-अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर-नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल।

जम्मू। कड़ी सुरक्षा के बीच, जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मंच तैयार है। पहले चरण में, चिनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। 26 सीटों के लिए दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को और 40 सीटों के लिए तीसरे चरण का चुनाव 5 अक्टूबर को होगा। इस बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में, 566,000 युवाओं सहित लगभग 2.3 मिलियन मतदाता चुनाव के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों को बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था द्वारा सुरक्षित किया जाएगा और इसमें केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ), जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस और जेके पुलिस की तैनाती शामिल होगी। अनंतनाग जिले में 64 उम्मीदवार, पुलवामा में 45, डोडा में 27, कुलगाम में 25, किश्तवाड़ में 22, शोपियां में 21 और रामबन में 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। किश्तवाड़ जिले में 48-इंदरवाल एसी में नौ उम्मीदवार, 49-किश्तवाड़ एसी में सात और 50-पैडर-नागसेनी एसी में छह उम्मीदवार मैदान में हैं।

बुधवार को जम्मू-कश्मीर के सात जिलों की 24 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडित दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले चरण के चुनाव में कश्मीरी पंडित समुदाय के छह उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। संजय सराफ अनंतनाग सीट से लोक जनशक्ति पार्टीके उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही शंगस-अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वीर सराफ, अपनी पार्टी के एमके योगी और निर्दलीय दिलीप पंडित मैदान में हैं।

राहुल बाबा झूठ बोलने की एक बड़ी मशीन:शाह

भिवानी। हरियाणा के भिवानी में चुनावी प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राहुल बाबा ने उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन किया है। उनका कहना है कि वे चुनाव के बाद सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे, पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे और आतंकवाद के कारण प्रतिबंधित संस्थाओं से प्रतिबंध हटा लेंगे। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा सुन लो हमारी बात, जब तक ऊपर पीएम मोदी बैठे हैं और बीजेपी है तब तक कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता।

शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि राहुल गांधी हम तो वो पार्टी हैं, जो मानती है कि पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कहने और देखने में तो छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली के नजदीक है। परंतु पूरा देश हरियाणा को 3 बातों के लिए याद करता है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद मोर्चे पर जितने भी जवान गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जवान हमारी इस वीरभूमि हरियाणा से गए हैं।

उन्होंने कहा कि जब देश में खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, देश को जब जरूरत पड़ी उस समय खाद्यान्न के भंडार भरने का काम भी मेरे हरियाणा के किसान ने किया है। अभी ओलंपिक और पैरालंपिक हुए। जब भारत का नाम उस तालिका में आता है, तो हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए और पूरे देश की भूख मिटाने के लिए अनाज देने का काम भी हमारे हरियाणा ने ही किया है।

मुख्यमंत्री से केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कुमार स्वामी ने सौजन्य मुलाकात की

सीएसआर मद के कार्यों को और अधिक गति देने की आवश्यकता: साय

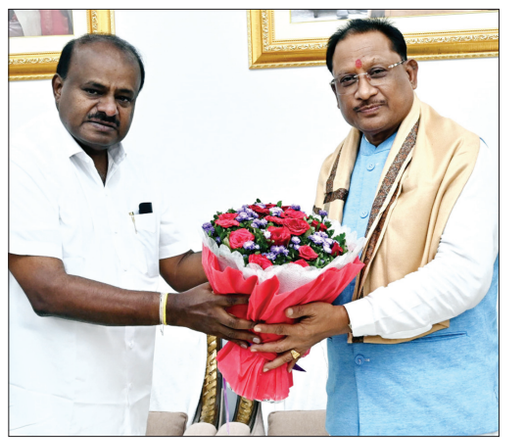

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहां उनके निवास में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का अपने निवास में आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कुमारस्वामी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान सेल और एनएमडीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने, दोनों उपक्रमों और राज्य सरकार के मध्य और बेहतर समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों उपक्रमों सेल और एनएमडीसी को सीएसआर मद के कार्यों को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगरनार अंचल में स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन के अधिक से कार्य किए जाएं, ताकि युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आये केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करने के बाद आज राजधानी रायपुर पहुंचे। सेल के चेयरमेन अमरेन्दु प्रकाश, एनएमडीसी के सीएमडी अमिताव मुखर्जी, मुख्यमंत्री और खनिज साधन विभाग के सचिव पी.दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस. और राहुल भगत, भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रमुख समाचार

रूस, यूक्रेन के बाद अब मोदी चले अमेरिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21-23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के अमेरिकी पक्ष के अनुरोध के बाद, भारत ने 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की है। क्वाड शिखर सम्मेलन में नेता पिछले एक वर्ष में क्वाड द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा निर्धारित करेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है।

उप्र से दंगे और दंगाई गायब लेकिन उनके आका परेशान

लखनऊ। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान हैं। योगी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि बांटने वाली राजनीति की जा रही है जो जाति के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। योगी ने कहा कि हमें मानना होगा सुरक्षा भविष्य की पहली आवश्यकता है। पर्व त्योहार व सभी कार्यक्रम सुरक्षित तरीके से मनाए जाएं ये हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें लूटो और अपना पेट भरो तक ही सीमित थी। इसी से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट उत्पन्न हुआ। किसान आत्महत्या करते थे, युवा पलायन करते थे, गरीब भूखे मरते थे, उद्यमी और बेटी सुरक्षा की गुहार लगाते थे ऐसा दृश्य दिखता था। मगर, आज उत्तर प्रदेश का और प्रदेशवासियों का सम्मान बढ़ा है।

फिर भी पप्पू ही रहा...खरगे के पत्र पर, रवनीत की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उन्होंने (कांग्रेस ने) उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, लेकिन फिर भी पप्पू (राहुल गांधी) पप्पू ही रहा...अन्य नेताओं को सिखाने के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने पप्पू (राहुल गांधी) को सिखाना चाहिए। बिट्टू ने कहा कि उन्हें (राहुल गांधी को) बोलने से पहले सोचना चाहिए...मेरी चिंताएं एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिख के तौर पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत उन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 'आपत्तिजनक एवं हिंसक' बयान दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर लिखे पत्र में उन्हें बधाई देने के साथ ही बिट्टू और सत्तापक्ष के कुछ अन्य नेताओं के राहुल गांधी के खिलाफ बयानों का उल्लेख किया और कहा कि ये भविष्य के लिए घातक हैं। खरगे ने अपने पत्र में कहा कि सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं।

न्यूयॉर्क के मंदिर में तोड़फोड़ की अमेरिकी सांसदों ने की निंदा

न्यूयार्क। के दोनों प्रमुख दलों के सांसदों ने न्यूयॉर्क में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि देश को सभी तरह की नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। न्यूयॉर्क के मेलविले में स्थित बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर के बाहर की सड़क और साइनबोर्ड पर सोमवार को अपशब्द लिखे हुए थे। बीएपीएस पब्लिक अफेयर्स ने एक पोस्ट में कहा कि मंदिर का अपमान होते देख उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने इसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास करार दिया। इसमें आगे कहा गया, आज स्थानीय, राज्य और संघीय नेता शांति, सम्मान और एकता को बढ़ावा देने के लिए एकत्र हुए। हम नफरत के खिलाफ एकजुट हैं। मेलविले, लॉन्ग आइलैंड पर स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को यहां एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं।

महिलाओं को रियायत नहीं समान अवसर चाहिए: अदालत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार का रैटियर साथी कार्यक्रम आपत्तिजनक है। इस नीति के तहत महिलाओं के काम के घंटे एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होने और रात की ड्यूटी से बचने का निर्देश दिया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना कैसे जारी कर सकती है। पीठ ने कहा कि अगर पुरुष 12 घंटे से अधिक समय की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो महिला डॉक्टर भी ऐसा करने की हकदार हैं। तीन जजों की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को अधिसूचना में तत्काल सुधार करने को कहा। शीर्ष अदालत ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात की शिफ्ट में काम नहीं करेंगी? अगर आप उन्हें रात में काम करने से रोकेंगे तो महिलाओं को आपत्ति होगी। महिलाओं को रियायत नहीं समान अवसर चाहिए। हमें एक महिला डॉक्टर को रात में काम करने से क्यों रोकना चाहिए? का कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना है आप यह नहीं कह सकते कि महिलाएं (डॉक्टर) रात में काम नहीं कर सकती हैं।

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा का दांव

अवधेश कुमार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद अचानक इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आखिर जो नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद छोडने को तैयार नहीं वह जमानत के बाद ऐसा करेगा इसकी कल्पना की भी कैसे जा सकती है।

अरविंद केजरीवाल की राजनीति कभी ऐसी धारा और धुरी पर नहीं चलती कि आप उनके अगले कदम का अनुमान लगा सकें। उन्होंने घोषणा कर दी लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। इसके लिए भी उन्होंने 48 घंटे का समय दे दिया। यानी देश 48 घंटे में कल्पना करता रहे कि वह क्या करेंगे, इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा करेंगे और सबकी दृष्टि उनकी ओर लगी रहे। अगर जेल से वो इस्तीफा दे देते तो इस तरह का माहौल निर्मित कर देना संभव नहीं होता। अगले वर्ष के आरंभ में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। निश्चित रूप से उनकी राजनीति उस पर केंद्रित होगी और लगातार वह इसी तरह चर्चा में बने रहने के लिए कुछ अकल्पनीय करते रहेंगे।

अन्ना अभियान से लेकर अभी तक उनकी राजनीति, तौर-तरीकों, चरित्र आदि पर नजर रखने वालों के लिए इसे पचा पाना कठिन हो रहा था कि जमानत पर आने के बाद अरविंद केजरीवाल इस तरह सामान्य गतिविधियों तक सीमित हैं। वह आगे क्या करेंगे इसके बारे में भी कोई टिप्पणी करना जोखिम भरा होगा। प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह जिस दिशा में घटना को बनाए रखना चाहते हैं वही बने और निश्चित तौर पर वही बनी रहेगी?

पहले प्रश्न का सरल सीधा उत्तर यही है कि जमानत मिलने के बावजूद न वे कैबिनेट की बैठक बुला सकते थे, न सचिवालय जा सकते थे, न मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते थे। यानी जमानत पर रिहा होना उनके लिए पूर्ण राहत का विषय नहीं था। अगर चुनाव के बीच लोगों को प्रलोभन या लुभाने के लिए घोषणाएं करनी हैं तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभानी होगी। हाथ पूरी तरह बंधे होने पर वह कुछ नहीं कर सकते थे।

अगर वह वाकई इस्तीफा देते हैं तो इसका एक प्रमुख कारण यही माना जाएगा कि इसके अलावा उनके पास अपनी पार्टी की चुनावी राजनीति की दृष्टि से कोई विकल्प नहीं था। भले वे पद पर न रहें, मुख्यमंत्री कोई भी हो असली नीति निर्धारक वही होंगे। केवल फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे किंतु निर्णय और शब्दावली उन्हीं की होगी।

न्यायालय ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके सचिवालय जाने पर रोक लगाई है। क्या वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी सचिवालय जाने या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर उनके लिए रोक होगी? इस्तीफा देने को इस तरह पेश कर रहे हैं जिससे जनता की पूरी सहानुभूति उनके साथ हो और चुनाव तक उनकी यही कोशिश जारी रहेगी। उनको अपने अनुरूप जेल से निकल कर राजनीति करने में कोई समस्या भी नहीं थी। अस्वीकार्य शराब नीति और भ्रष्टाचार के आरोपों में काफी हद तक दिखती सच्चाई के होते हुए दिल्ली की मुख्य पार्टी भाजपा ने अगर यह स्थिति पैदा नहीं की कि केजरीवाल और 'आप' को रक्षात्मक या बचाव की मुद्रा अपनानी पड़े तो फिर उनके सामने अपनी राजनीति को अपने अनुसार मोड़ देने के लिए खुला मैदान है।

अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे और भाजपा इसे दिल्ली की जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा नहीं बना सकी। भाजपा जैसी दिल्ली में इतनी ठोस आधार वाली सशक्त पार्टी की दशा ऐसी है तो केजरीवाल और उनकी पार्टी को विवश करने वाली चुनौती कौन दे सकता है? ध्यान रखिए, दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप पहले कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने लगाया था। किंतु कांग्रेस दिल्ली में जिस लुंज-पुंज, दुर्बल अवस्था में है उसमें वह उन्हें घेर कर बचाव की मुद्रा में आने के लिए विवश नहीं कर सकती। वैसे भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस समय आई.एन.डी.आई.ए. के माध्यम से भाजपा और नरेंद्र मोदी को पराजित करने की सोच तक सीमित राजनीति कर रहा है। उसमें उसके किसी घटक के विरुद्ध एक सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अवश्य अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर तार्किक प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं पर व्यावहारिक राजनीति में उसके कोई मायने नहीं हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अरविंद या उनकी पार्टी के विरुद्ध किसी आंदोलन या लम्बे अभियान की अनुमति नहीं दे सकता। आप सोचिए, केजरीवाल और मनीष सिसौदिया दोनों दिल्ली के मोहल्ले-मोहल्ले में जाएंगे और लोगों के बीच बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा हमारी सरकार और पार्टी को खत्म करने के लिए कानूनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जबकि हम लोग निर्दोष हैं। तो उसी भाषा या उससे ज्यादा प्रभावी भाषा में जनता के बीच जाकर प्रत्युत्तर देने या खंडन करने का स्वाभाविक कार्यक्रम क्या दिल्ली की दूसरी राजनीतिक धारा ने बनाया है?

अरविंद केजरीवाल जैसी चाहेंगे वैसी राजनीति करेंगे, वो अपनी शैली में व्यापक वर्ग को यह समझाने में सफल भी हो सकते हैं कि वाकई वे निर्दोष हैं तथा भाजपा सत्ता की ताकत से उनको खत्म करना चाहती है। हालांकि यह हमारा दुर्भाग्य है और भारतीय राजनीति की दिल दहलाने वाली त्रासदी भी कि सामान्य सिद्धांतों, मूल्यों और विचारधाराओं तक को ताक पर रखकर लोगों को मोहित करने की शैली में कोई सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में सफल हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने जमानत के साथ सार्वजनिक तौर पर मुकद्दमे पर कोई बयान न देने की शर्त लगाई है किंतु वह बयान दे रहे हैं और उस पर कोई रोक नहीं।

बाढ़ के पानी ने गांव में मचाई तबाही डायरिया से 55 लोग हुए बीमार

बालोद। बालोद जिले के गुरूर ब्लाक अंतर्गत ग्राम बगदाई में डायरिया ने पैर पसार लिया है दरअसल यहां पर बाढ़ के हालातो के कारण पेयजल वाले पाइपलाइन में गंदा पानी चला गया था जिसके कारण उल्टी दस्त की शिकायत हुई फिर डायरिया का मामला सामने आया है जिसके बाद समय रहते स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर कैंप लगाकर अति गंभीर लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जिसके बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सुनील भारती ने बताया कि आज 1 मरीज सामने आए थे जिनका इलाज किया गया है और रिफर किया गया था एक दिन पूर्व 8 मरीज उसके पहले 10 मरीज ऐसे करते यह आंकड़ा 55 तक जा पहुंचा।

प्राथमिक उपचार के लिए विकासखंड स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पंचायत में ही कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रही है वहीं गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सुनील भारती ने बताया कि तीन दिन पहले यहां की स्थिति काफी देनी है थी और अब तक मरीज 55 हो चुके हैं आज केवल एक ही मरीज सामने आए हैं और पानी में जो समस्या थी उसे भी अब सुधार लिया गया है।

डॉक्टर ने बताया कि यहां पर बाढ़ आया हुआ था और पाइपलाइन जो फटा हुआ था उसके माध्यम से बाढ़ का गंदा पानी टंकी में चला गया जिसका शुद्धिकरण नहीं हो पाया था और उसके कारण डायरिया फैलने की बात सामने आई जिसके बाद पानी को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया था उसके बाद अब शुद्धिकरण कर लिया गया है उन्होंने कहा कि यदि पानी गंदा हो तो हमें उसे उबालकर पीना चाहिए इस गांव में भी यही स्थिति सामने आई बारिश के बाद जो बाढ़ का गंदा पानी भाकर आया था वह किसी न किसी माध्यम से पाइपलाइन तक जा पहुंचा था और घरों तक भी जा पहुंचा जिसके बाद बीमारी ने पैर पसार लिया उन्होंने कहा कि अभी हम कैंप लगाकर यहां पर इलाज कर रहे हैं।

सरपंच निलेश्वरी साहू ने बताया कि जब दो दिन पूर्व यहां पर डायरिया की शिकायत आई तो हमने इतिहास के तौर पर पानी का सैंपल लेकर पीएचई विभाग को भेजा था जिसके बाद रिपोर्ट सामने आया कि पानी दूषित होने के कारण डायरिया फैला हुआ है स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया गया स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर कैंप लगाया अपना टीम भेजा इसके बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है उन्होंने कहा कि अब हमारे गांव में घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है और यदि कोई गंभीर मरीज सामने आता है तो हम उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहां से भिजवा रहे हैं।

सरपंच ने बताया कि जो पुराना पाइपलाइन जो फटा हुआ था उसे सुधारा जा रहा है और नई पाइप लाइन से भी सप्लाई की जा रही है ताकि दूसरी पानी का नुकसान और लोगों को ना हो जो भी संभव हो पा रहा है पंचायत हम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है समय रहते हमारे गांव में सुधार ला लिया गया है और डायरिया के मरीज आने कम होने लगे हैं आज केवल एक ही मरीज सामने आया था।

सांसद ने 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का किया शुभारंभ

जगदलपुर। सांसद महेश कश्यप ने आज जगदलपुर शहर के शहीद पार्क परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहीद पार्क परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती सफीरा साहू, पार्षदगण, कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर निगम हरेश मंडावी और गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण, युवोदय की टीम, नगर निगम के टीम, पत्रकारगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

जिले में 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए सांसद कश्यप ने कहा कि स्वच्छता मानव जीवन का जरुरी हिस्सा है, हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। शहरों, गांवों एवं प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जगदलपुर विधायक किरणदेव को आज उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना दीं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा कि 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा में शहर के नागरिक अपने घरों के आसपास साफ- सफाई रखें। साथ ही जागरूकता के माध्यम से जगदलपुर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों ने पार्क में सफाई अभियान किया।

ज्ञात हो कि 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर आज से राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश

जगदलपुर। फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप के जरिए लाखों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह का बस्तर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 सदस्यों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। बस्तर पुलिस के अनुसार, दुबई से संचालित गिरोह इन्वेस्टमेंट स्कैम को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, अब तक इस गिरोह के खिलाफ देशभर में 6 करोड़ रुपये की ठगी की एफआईआर दर्ज किया जा चुकी है।

गिरोह सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट एप का विज्ञापन के जरिए लोगों तक पंहुचता है। इसके बाद ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर बड़ी राशि इन्वेस्ट करा ली जाती है। गिरोह के लोग पैसों को कई खातों के माध्यम से सूरत में कलेक्ट करते हैं। इन पैसों को आखिर में दुबई तक पंहुचाया जाता है। दुबई में निखिल नाम के हैंडलर द्वारा इस पूरे गिरोह को संचालित करने की जानकारी पुलिस को लगी है।

धान बेचने के बाद भी सहकारी समिति ने किसान को नहीं किया था भुगतान

10 साल बाद हाईकोर्ट से मिला न्याय

बिलासपुर। धान बेचने के बाद भी सहकारी समिति ने किसान को भुगतान नहीं किया था। दस साल कानूनी लड़ाई के बाद किसान को न्याय मिल सका। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समिति ने 3 लाख 45 हजार का चेक प्रदान किया।

मुंगेली जिले के सारधा निवासी तोपसिंह राठौर ने वर्ष 2014 में सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लोरमी में उत्तम क्वालिटी का 525 बोरा धान तौल कराकर जमा कराया। इसके बाद भी कई साल तक इन्हें भुगतान के लिए भटकाया जाता रहा। 2.08.2019 को उप पंजीयक सहकारी समिति मुंगेली ने पत्र द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित लोरमी के अध्यक्ष/प्रबंधक को मामले की जांच कर भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लोरमी को निर्देशित किया कि, वह इस आदेश की मिलने के 15 दिनों के भीतर बोनस के साथ वर्ष 2014 में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले धान की 525 बोरियों का भुगतान करें। निर्धारित अवधि बीतने पर भी कोई भुगतान नहीं हुआ, तो किसान ने दोबारा अपने अधिवक्ता के जरिये अवमाना याचिका लगाई। जस्टिस एन के व्यास की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट को बताया गया, कि याचिकाकर्ता को 3 लाख 45 हजार 500 रूपये चेक के जरिए भुगतान किया जा चुका है। कोर्ट ने आदेश दिया, कि समिति से मिले चेक से भुगतान न होने पर वह दोबारा हाईकोर्ट आ सकता है।

बिलासपुर की सड़कों पर दिखा फिलिस्तीन का झंडा

- हिंदू जागरण मंच ने जताया विरोध

बिलासपुर। बिलासपुर के तारबाहर इलाके में सड़क पर फिलिस्तीन का झंडा लहराता नजर आया।जब इस पर हिंदू जागरण मंच की नजर पड़ी तो विरोध शुरु हुआ। हिंदू जागरण मंच ने इसकी शिकायत पुलिस से की।जिसके बाद पुलिस ने सड़क के बीच में लगे झंडों को उतारा और झंडा लगाने वाले लोगों को तलाश शुरु की।

आपको बता दें कि सोमवार रात ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर लोग जश्न के माहौल में थे। लेकिन तारबाहर इलाके में फिलिस्तीनी झंडे ने लोगों के रंग में भंग डालने का काम किया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरु किया। इस मामले में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तारबाहर थाने के पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची और झंडा को उतरवाया।

वहीं हिन्दू जागरण मंच के पार्थ मुखर्जी ने कहा कि व्यापार विहार से तारबाहर तरफ आने

वाले रोड पर फिलिस्तीनी झंडे काफी सारे लगे हुए थे। इसकी सुचना हमें मिली।हमने थाना प्रभारी के संज्ञान में इस घटना को लाया।

पार्थ मुखर्जी ने कहा बिलासपुर जैसे शांत शहर में फिलिस्तीन जैसे मुल्क का झंडा हमारे शहर की शांति को भंग करने का षडयंत्र है।ये झंडे सुनियोजित तरीके से लगाए गए हैं।हमारे शांत शहर मे ऐसा मामला सामने आया है जो चिंता का विषय है।

वहीं इस पूरे मामले में तारबाहर थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने मीडिया को फोन पर घटना के बारे में जानकारी साझा की। गोपाल सतपथी के मुताबिक फिलिस्तीनी झंडे के निशान की तरह एक झंडा लगा हुआ था। सूचना पर हमने झंडे निकलवाए हैं और मामले की जांच में जुटे हैं।

सरपंच पति से एक लाख रुपये की रिश्वत लेने वाला अकाउंटेंट सस्पेंड

- एसीबी ने किया था गिरफ्तार

कबीरधाम। बीते 12 सितंबर की देर शाम को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने कबीरधाम जिले में दबिश दी थी। इस टीम ने बोड़ला जनपद पंचायत के अकाउंटेंट नरेन्द्र कुमार राउतकर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। प्रार्थी मोती बैगा, ग्राम कुकरापानी, तहसील बोड़ला ने एंटी करप्शन ब्यूरो के रायपुर कार्यालय में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी ग्राम पंचायत कुकरापानी की सरपंच है।

शासन द्वारा उनके ग्राम पंचायत को आंगनबाड़ी भवन कार्य के लिए 11.69 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। धनराशि का आहरण जनपद पंचायत बोड़ला कार्यालय से होना था। लगभग 5.84 लाख रुपए ग्राम पंचायत को जारी भी कर दिए गए थे। लेकिन, जनपद कार्यालय के अकाउंटेंट नरेन्द्र कुमार राउतकर द्वारा अगली किश्त जारी करने के एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। इस मामले में एसीबी ने कार्रवाई कर आरोपी को

जेल भेज दिया है।

वहीं आज 17 सितंबर को अकाउंटेंट नरेन्द्र कुमार राउतकर को कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जनपद पंचायत बोड़ला के सीईओ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सस्पेंड किया है। एसीबी के रिमांड में लेकर अपने अभिरक्षा में रखे जाने व गिरफ्तारी अवधि 48 घंटे से अधिक होने के कारण छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 निलंबन नियम 9 (2) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में अकाउंटेंट नरेन्द्र कुमार राउतकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

एसीबी की कार्रवाई में गिरफ्तार अकाउंटेंट नरेन्द्र कुमार राउतकर का विवादों से गहरा नाता रहा है। यह बोड़ला में ही करीब 33 वर्ष से पदस्थ है। वर्ष 2021 में जनपद पंचायत बोड़ला में पदस्थ नरेन्द्र कुमार राउतकर के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। इसने फर्जी तरीके ने न सिर्फ अपने भतीजे की सहायक ग्रेड-3 पद पर नौकरी लगाई, बल्कि बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर पहले से काम रहे चार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से पांच-पांच लाख यानी कुल 20 लाख रुपए घूस लेकर उन्हें रेगुलर (नियमित) करने का आरोप लगा था। उन्हें एक साल का वेतन सहित एरियर्स का भी भुगतान कर दिया था। हालांकि, उस समय कलेक्टोरेट से जांच बैठाई गई थी। तब सस्पेंड किया गया था। अब एसीबी के कार्रवाई बाद सस्पेंड हुआ है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बैक फुट पर एसडीएम, निलंबित पटवारी को किया बहाल

गरियाबंद। देवभोग में निलंबित पटवारी को बहाल कर दिया गया है। बहाली के साथ ही एसडीएम ने पटवारी का तबादला कर दिया है। इससे पटवारी आहत है और कहा ये निलंबन से बड़ी सजा है। दरअसल देवभोग तहसील पटवारी संघ के दिए गए चेतावनी के मुताबिक आज अतिरिक्त हल्का का बस्ता सौंपने पटवारी पहुंचे तो एसडीएम तुलसी दास ने उन्हें निलंबित पटवारी नटेश्वर नायडू की बहाली आदेश दिखा दिया। लेकिन इस आदेश में पटवारी नायडू को लाटापारा हल्का के बजाय हल्का 18 दीवानमुड़ा व हल्का 23 डूमर का कार्य दे दिया गया। इस आदेश को पटवारी संघ ने न्याय संगत नहीं माना और रिसीव नहीं किया। पीड़ित पटवारी नायडू ने कहा की बहाली का यह आदेश निलंबन से बड़ी सजा के बराबर है। कारण बताते हुए कहा कि पिछले डेढ़ माह से गिरदावरी का काम जारी है और हल्का में वो 80 फीसदी कार्य कर चुके हैं। निर्देश के मुताबिक 15 दिन के भीतर गिरदावरी कार्य को पूर्ण कर के देना है। यकायक दो नए हल्का में जाकर गिरदावरी जैसे कार्य को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा।

चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा

सूरजपुर। छत्तीगसढ़ के सूरजपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां चोरी के शक में एक युवक को बंधक बनाकर तालिबानी सजा दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भटगांव पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि यह वायरल वीडियो जिले के एसईसीएल क्षेत्र भटगांव के सब एरिया मैनेजर ऑफिस का है। जहां काम करने वाले मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित तीन गार्डों ने मिलकर भटगांव के ही रहने वाले शुभम जायसवाल को चोरी का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे बंधक बनाकर तीनों ने जमकर पिटाई की, इस दौरान आरोपियों ने पिटाई का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, संतोष महतो ने बतया कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसपर संज्ञान लेकर भटगांव पुलिस को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था।

एक ही फंदे पर लटकी मिली युवक और युवती

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर युवक और युवती की एक ही फंदे से लटकी हुई लाश मिली है मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है और उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है दरअसल सुबह-सुबह कुछ ग्रामीणों ने उसे लाश को देखा उसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी फिर मामला थाने तक पहुंचा जिसके बाद थाना प्रभारी रविशंकर पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों लाश को सुरक्षित निकाला गया और सब का पंचनामा किया गया है पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है कोतवाली थाना क्षेत्र के तालगांव-रानीमाई मार्ग के समीप जंगल में इस घटना को अंजाम दिया गया है। आसपास की ग्रामीणों की माने तो यह प्रेमी जोड़ा हो सकता है और लाश को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक-दो दिन पूर्व आत्महत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया होगा फिलहाल पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो।

राइसमिल गोदाम में लगी भीषण आग

दुर्ग। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में स्थित नमन फूड प्रोसेस राइसमिल में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की सूचना राइसमिल के मालिक ने पुलिस और जिला अग्निशमन की दी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की ती से चार गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आग से राइसमिल मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। जिला अग्निशमन विभाग के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड कि टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने में जुट गई। जिला दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया था। जहां आग काफी बड़ी थी। दमकल को टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा है। आग शॉर्ट सर्किट से लगाने की आशंका जताई जा रही है। इस आग से राइसमिल मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। आग से राइसमिल में धान, बारदाने और भूसी जलकर खाक हो गए हैं।

जमीन विवाद में हुई युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जगदलपुर। बस्तर जिले के बड़ाजी थाना क्षेत्र के ग्राम राउतपारा में बीती रात जमीन विवाद को लेकर एक युवक ने अपने ही परिवार के युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी की खोजबीन की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि राउतपारा निवासी परमेश्वर यादव पिता मुन्ना लाल 25 वर्ष बीती रात अपनी मां ललिता को लेकर अपने ही रिश्तेदार के घर पहुंचा। जहां बताया कि विगत पांच वर्षों से जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इसके अलावा जमीन का बंटवारा होने के बाद ही क्षमता से अधिक जमीन को ले लिए हो। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा की मारपीट के बाद आरोपी ने घर में रखे कुल्हाड़ी से परमेश्वर के ऊपर हमला कर दिया। जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया।

बेमेतरा में कांग्रेसी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बीच मारपीट

- दोनों पक्षों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा गणेश पंडाल के कार्यक्रम में गए हुए थे। इस दौरान उन्हें काला झंडा दिखाने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी मामले को लेकर देर रात कांग्रेसियों और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई।

घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष

अमित बघेल देर रात बेमेतरा पहुंचे और थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। वहीं कांग्रेसियों ने भी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि बेरला थाना क्षेत्र के सरगा गांव में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यक्रम में क्रांति सेना के कार्यकर्ता काला झंडा दिखाने पहुंचे थे। इस पर पहले गांव वालों ने मना किया। उसके बाद इसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के बीच विवार हुआ। मारपीट भी हुई। इस मामले में फिलहाल बेरला थाने और कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही। वहीं आरोपियों की पतासाजी भी की जा रही है।

जशपुर की बबीता के दिल का हुआ सफल ऑपरेशन

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में लगायी थी फरियाद, चिरायु टीम के माध्यम से एम्स में हुआ ऑपरेशन

जशपुर। जशपुर की 10 वर्षीय बालिका बबिता को माता-पिता ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया पहुंचकर बच्ची के ईलाज के लिए फरियाद लगायी। यह बच्ची गुमसूम रहती थी, खेलने-कूदने में भी इसे दिक्कत होती थी। कैम्प कार्यालय के निर्देश पर इस बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण हुआ। परीक्षण में चिकित्सकों ने दिल में छेद होने की आशांका जतायी और बालिका को समुचित उपचार करने के लिए उनके माता-पिता को समझाईश दी गई। जिला प्रशासन जशपुर और चिरायु टीम के जरिए बबिता के दिल का एम्स रायपुर में सफल ऑपरेशन हुआ। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। उसे कैम्प कार्यालय के जरिए नया जीवन मिला है। बबिता के माता-पिता बच्ची के हृदय में छेद होने की जानकारी मिलने पर बहुत चिंतित हो गए थे। लेकिन जिला प्रशासन और कैम्प कार्यालय की मदद से उनकी दिक्कत दूर हो गई।

चिरायु टीम के अमित भगत ने बताया बचपन से बबीता को दिल में छेद था, सांस लेने और दौडने भागने में भी दिक्कत आती थी। बबीता की मां जय कुमारी बाई और पिता झमेश राम ने बताया कि उनकी बेटी को जन्म से दिल में छेद होने का अंदेशा था। लेकिन आर्थिक तंगी और ईलाज में होने वाले खर्च को लेकर भी उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी। जैसे ही उनका आवेदन कैम्प कार्यालय को मिला मुख्यमंत्री ने तत्काल बबीता का ईलाज करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन और चिरायु टीम बच्ची के घर जाकर पालकों से सम्पर्क किया और ईलाज की व्यवस्था की गई। बबीता के माता-पिता ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सार्थक प्रयास से उनकी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई है। वर्तमान में कक्षा 6वीं में पढ़ाई कर रहीं हैं। स्कूल आने जाने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। अपनी बच्ची को हंसता मुस्कुराता देखना अच्छा लगता है।

संक्षिप्त समाचार

सीएम विष्णु देव साय ने श्रमेव जयते वेबसाइट किया लॉन्च

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में पहुंचे थे। जहां उन्होंने श्रमेव जयते वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये एक शिकायत निवारण ऑनलाइन प्रणाली ऐप है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिक अपनी समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। श्रमिक 87713505050 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। शिकायत का निराकरण न होने पर स्वत: ही उच्च अधिकारियो को प्रेषित हो जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कृषि मंडपम और राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में पहुंचे थे। ये सम्मेलन उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, विधायक गुरू खुशवंत साहिब मौजूद थे। सीएम कुछ ही देर में श्रमिको को राशि जारी करेंगे।

भगवान श्री गणेश के पूजन-हवन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने यहां

अपने निवास में विराजे भगवान श्री गणेश का पूरे विधि-विधान से पूजन-हवन किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृध्दि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रदेशवासियों को अंनत चतुर्दशी की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के परिवारजन व अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने

मंगलवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में पूर्ण विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने संसार के प्रथम वास्तुकार, निर्माण और सृजन के देवता, भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर सभी श्रमवीरों सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा और मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि, हमारे श्रमवीर छत्तीसगढ़ को गढने में सार्थक भागीदारी निभा रहे हैं। श्रम से सृजन की सार्थकता को विश्वकर्मा जी ने ही समाज में स्थापित किया। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें श्रम के लिए संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। विश्वकर्मा जी का तकनीक कौशल और श्रमशीलता प्रेरणादायी है।

साव ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी परिवारों को गृहप्रवेश पर दी बधाई

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 23 हजार 071 लाभार्थी परिवारों को आज अपने नए आशियाने में प्रवेश पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में देश के चार लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित मकानों में गृहप्रवेश करा रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के 68 नगरीय निकायों के 23 हजार 071 परिवार भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास के बीच वहां से भेजे संदेश में सभी लाभार्थी परिवारों को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा है कि आज आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आप लोगों का गृहप्रवेश कराने वाले हैं। श्री साव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की हैं कि आप इसी तरह लोगों का जीवन आसान बनाते रहें और लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें।

डाक्टर राकेश गुप्ता को मिली धमकी

रायपुर। डाक्टर राकेश गुप्ता ने आज एसपी से मिलकर शिकायत दर्ज करायी है जिसमें उन्होने कहा है कि माननीय हाईकोर्ट व एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार राज्य शासन द्वारा डीजे के शोर को नियमानुसार नियंत्रित करने के आदेश किए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होने भी अपने साथियों के साथ इस आदेश का स्वागत किया है। आज सुबह उन्हे पता चला कि डीजे संचालकों के समूह में उनका नाम लेकर धमकियां दी जा रही है और किसी प्रकार अनहोनी की बात कही गई है। कृपया संज्ञान में लें और उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने हेतु कदम उठाएं। उन्होने अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। एसपी ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेने का आश्वासन डाक्टर गुप्ता को दिया है।

स्वच्छता को बनाए सामाजिक आंदोलन, जन-जागरूकता से ही स्वच्छ होगा प्रदेश : साय

मुख्यमंत्री ने 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का किया राज्य स्तरीय शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेलीबांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने स्वच्छता दीदियों तथा शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाले सामाजिक संस्थाओं ग्रीन आर्मी, बंच ऑफ फूल्स, कुछ फर्ज हमारा भी और एवेंजर्स ग्रुप के साथ ही समाज सेविका श्रीमती शुभांगी आप्टे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के शुभारंभ पर आयोजित स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नए स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा तथा महापौर श्री एजाज ढेबर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। शहरों, गांवों एवं प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है। जन-जागरूकता से ही प्रदेश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। उन्होंने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना दीं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। इसके बाद से ही घर-घर में शौचालय बनाने के लिए सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। जनधन योजना के तहत देशभर में लोगों के बैंक खाते खुले। इन

खातों में सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि बिना किसी लीकेज के हितग्राहियों तक पहुंच रही है। इन राशियों का बहुत बेहतर सदुपयोग भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं स्वच्छता दीदियों को शत-शत नमन करता हूं। वे घर-घर जाकर कचरे का संग्रहण कर रही हैं और स्वच्छता में महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रही हैं। वे सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कर रिसायक्लिंग और खाद बनाने के लिए भेज रही हैं। श्री साय ने बताया कि उन्हें कल गुजरात में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में शामिल होने का अवसर मिला था, जिसमें वायुमंडल को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा की जानकारी देते हुए कहा कि 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' की थीम पर आज से राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वच्छता दीदियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही मैराथॉन, साइक्लोथॉन, श्रमदान जैसी विविध गतिविधियां संचालित की जाएंगी। 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के शुभारंभ के मौके पर रायपुर संभाग के आयुक्त श्री महादेव कावरे, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी श्री संतोष सिंह और नगर निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री साय ने किया जनसंपर्क की प्रदर्शनी का शुभारंभ

बीते 10 सालों में शुरू की गई योजनाओं को किया गया प्रदर्शित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनकल्याण एवं भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए बीते दस सालों में शुरू की गई अभिनव एवं क्रांतिकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के जीवन के पहलुओं को छाया-चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मंगलवार को जन्म दिन था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 5 लाख से अधिक परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि का अंतरण भी हितग्राहियों को डी.बी.टी. के माध्यम से खाते में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार

और राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इसके तहत् राज्य में 18 लाख से अधिक परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवास की स्वीकृति दी गई है।

छाया-चित्र प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए ''एक पेड़ मां के नाम'' वृक्षारोपण अभियान, डिजिटल इकोनॉमी-जन-जन को बैंकिंक सुविधा, नए अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरता भारत, आतंकवाद के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, औपनिवेशिक काल के कानूनों में बदलाव एवं नवीन न्याय संहिता को लागू करना, भारतीय सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, जन भागीदारी से देश को नई दिशा, भारत का गौरव बढ़ाती उपलब्धियां, जनधन योजना, देश में अधोसंरचना का तेजी से निर्माण, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एक ग्रिड,एक राशन कार्ड, एक संविधान और वोकल फार लोकल आदि विषयों को छाया-चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से जुड़े प्रसंगो को भी दर्शाया गया है।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह,गृह मंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उपस्थित थे।

आज होगा एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ

नई दिल्ली/रायपुर। केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली के साथ ही देश के लगभग 75 स्थानों पर एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य स्थानों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन में नए नाबालिग ग्राहकों को पीआरएएन सदस्यता का वितरण किया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा नाबार्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एनपीएस वात्सल्य योजना का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अपराह्न 01.30 बजे से 04.00 तक ब्रम्हविद ग्लोबल स्कूल, भटगांव, रायपुर, मंहत पोसुदास शासकीय हाई स्कूल, सुरपा-पाटन, जिला दुर्ग और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, तारबहार, बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे अपने पालकों के साथ शामिल होंगे।

सरकारी पुस्तकें रद्दी में, अब होगी जांच

- आईएएस राजेंद्र कटारा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम गठित

रायपुर। जिले के सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल के गोदाम में रविवार शाम को भारी मात्रा में सरकारी स्कूली किताबों का जखीरा बरामद किया था, जिन्हें छात्रों को बांटने की बजाए रद्दी में बेच दिया गया था। मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आज छग पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है।

मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। दरअसल पूरा मामला सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल के गोदाम का है जहां से भारी मात्रा में सरकारी स्कूल के किताबों का जखीरा बरामद किया गया है। मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है।

पेपर मिल के गोदाम में वर्तमान सत्र की सरकारी किताबों का जखीरा बरामद होने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने छग पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। दल में अतिरिक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय डॉ. योगेश शिवहरे, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग राकेश पांडेय, छग पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा और कलेक्टर को शामिल किया गया है।

सुकमा-कवर्धा हत्या मामले की जांच करेगी कांग्रेस पार्टी

- पीसीसी चीफ बैज ने बनाई 6-6 सदस्यों की टीम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और सुकमा जिले में हत्या-आगजनी मामले में कांग्रेस पार्टी ने जांच टीम की गठन की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर दोनों मामलों के लिए छह-छह सदस्यीय टीम की गठन की गई है। अब इस पूरे मामले में दोनों जांच कमेटी घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। साथ ही आसपास के लोगों से बात भी करेंगे। एक हफ्ते के भीतर पूरी जांच कर एक रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को भेजा जाएगा।

कवर्धा मामले में भी छह सदस्य जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू को संयोजक बनाया गया है। वहीं विधायक भोलाराम साहू, इंद्र शाह मांडवी, यशोदा वर्मा, संदीप साहू और कवर्धा जिला अध्यक्ष होरी राम साहू सदस्य बनाए गए हैं।

दूसरी ओर सुकमा जिले में हुई घटना को लेकर पार्टी ने जांच के लिए बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल संयोजक बनाया है। वहीं विधायक कवासी लखमा, विक्रम मांडवी, पूर्व विधायक रेखचंद जैन, पीसीसी सचिव दुर्गेश राय और सुकमा जिला अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल सदस्य बनाए गए हैं।

जानें क्या है पूरा मामला

सुकमा जिले में बीते दिनों जादू-टोने के शक में पूरे परिवार के सदस्यों को मौत के घात उतर दिया गया। मामला कोंटा के मुरलीगुड़ा कैंप के पास इटकल गांव का है। परिवार के पांच लोगों को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मारा गया।

शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ : राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों से विकास एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल श्री डेका ने जल संरक्षण एवं जल संचयन, पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन, परंपरागत एवं जैविक खेती प्रोत्साहन, टी.बी उन्मूलन, सड़क सुरक्षा आदि विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया।

राज्यपाल ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों एवं प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग करने एवं इसके इलाज को लेकर लोगों को जागरूक करने बात कही। उन्होंने रेडक्रॉस के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही रेडक्रॉस के चुनाव कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री डेका ने वृक्षारोपण को

लेकर विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि पौधे लगाने के साथ ही उसे जीवित रखने को लेकर समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने पौधरोपण के लिए जल्दी विकसित होने वाली पौधों की प्रजातियों के चयन की बात कही। राज्यपाल श्री डेका ने परंपरागत कृषि एवं जैविक खेती प्रोत्साहन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा देने किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। जिले के सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के रखरखाव के संबंध में जानकारी ली तथा ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़ी जानकारियां डिजिटल रूप से भी संग्रहित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने बैठक में कहा कि ड्रग्स एवम नशे के कारण युवा काफी प्रभावित हो रहे हैं इसके रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली।

राज्यपाल श्री डेका ने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडने एवं स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने कहा। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी गतिविधि बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि अंचल में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना के माध्यम से विकास मूलक कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए।

अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़ : दीपक बैज

- भाजपा नेता श्रीवास्तव बोले- कांग्रेस सरकार में हुआ ज्यादा अपराध

रायपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री धृतराष्ट्र बनकर घटनाएं देख रहे। लोगों का इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। डबल इंजन की सरकार नहीं, सुशासन और जंगल राज चल रहा है। बैज ने पूछा है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में क्यों सफल नहीं है। बैज के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि गृहमंत्री और मुख्यमंत्री से इसलिए इस्तीफा मांग रहे, ताकि ये फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए वापस आ जाए। कवर्धा की घटना पर श्रीवास्तव ने कहा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस सरकार में ज्यादा अपराध हुआ था।

दीपक बैज ने कहा, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया है। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। कवर्धा में हुई घटना पर सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ बैज ने कहा, गृह मंत्री के जिले में पुलिस के सामने घर जलाया गया। पुलिस अलर्ट होती तो घटना रोकी जा सकती थी। सरकार की नाकामी से दो लोगों की जान चली गई।

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस सरकार से अपराध की घटनाएं कम हो रही। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अकड़ें पेश करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक चश्मा उतार लें, गृहमंत्री को बर्खास्त करें। मुख्यमंत्री किस अकड़ें की बात कर रहे हैं? झीरम घाटी कांड, जादू टोने के शक में हत्या, घर जल रहे, एसपी-कलेक्टर ऑफिस जल गए, अंतर्राष्ट्रीय शूटर पैर पसार रहे, गोलियां चल रही, क्या हमारे सरकार में ये घटनाएं हुई? अपनी नाकामियों को छुपाने लिए अकड़ें पेश कर रहे हैं।

अलर्ट मोड पर है प्रशासन : संजय श्रीवास्तव

वहीं भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कथन यही है कि गृहमंत्री इस्तीफा दें। भाजपा इस्तीफा दें, ताकि ये फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए वापस आ जाए। एक कार्यकाल के लिए 15 साल बाद जनता ने इनके झूठे वादों पर भरोसा कर दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत को मौका दिया था। सभी ने आम जानता कि चिंता न करते हुए भ्रष्टाचार के तमाम दरवाजे खोल दिए। दीपक बैज को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दीपक बैज को अनुभव की कमी है। पढ़ते नहीं है केवल बोलते हैं। अपने आंकड़ों को देखते नहीं है। कांग्रेस सरकार में ज्यादा घटनाएं हुई है। यदि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो एनसीआरबी, प्रदेश, स्थानीय तमाम डेटा हम उपलब्ध करा देंगे। संजय श्रीवास्तव ने कहा, कवर्धा की घटना का हम समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

राजधानी रायपुर में 19 से होगा भव्य शिव महापुराण

रायपुर। राजधानी के सिद्ध पीठ श्री राजराजेश्वरी मां महामाया देवी मंदिर, पुरानी बस्ती में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कथावाचक आचार्य पंडित श्रीयुत युवराज पाण्डेय व्यासपीठ से कथा सुनाएंगे। इसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी जो 27 सितंबर तक चलेगी। मंदिर परिसर में कथा की भव्य तैयारी हो रही है। शिव महापुराण के आयोजक पंडित मनोज शुक्ला ने बताया की कथा रोज दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। 19 तारीख को पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर का भ्रमण करते हुए मंदिर वापस आयेगी। इसमें बड़ी संख्या में लोग कलश लेकर निकलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कलश यात्रा की भव्य तैयारी पूरी हो गई है। शिव महापुराण में 19 सितंबर को कलशयात्रा के बाद शिव महापुराण के महत्तम का वर्णन किया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को शिवपूजन विधि, भस्म धारण और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन आचार्य युवराज पाण्डेय व्यास पीठ से करेंगे। 21 को ब्रह्मनारद संवाद लोगों को जानने मिलेगा। 22 को दक्षतप, शिव का वरदान, सती जन्म और शिव विवाह से जुड़ी कई रोचक जानकारियां श्रोताओं को सुनने को मिलेंगी। 23 तारीख को सती देहत्याग, सतीमोह रामकथा और गंगा की उत्पत्ति से जुड़ी संगीतमय कथा का श्रवण लोगों को करने मिलेगा।

केजरीवाल के इस्तीफे के दांव से पूरी होगी महत्वाकांक्षा!

राजकुमार सिंह

चित कौन होगा—यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन शराब घोटाले में जमानत पर रिहा अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के दांव से चौंका सभी को दिया है। गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल का इस्तीफा मांगती रही भाजपा ने जमानत की शर्तों के आधार पर भी मांग दोहराई थी, पर आप ने साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिली और 15 सितंबर को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और मतदाताओं द्वारा जनादेश के जरिये उन्हें ईमानदार मान लेने के बाद ही पद लेंगे। यह भी कि चुनाव तक आप का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री पद संभालेगा। केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नवंबर में कराए जाएं। उनकी इच्छा कितनी पूरी होगी यह तो उनके इस्तीफे पर उप राज्यपाल और फिर चुनाव आयोग के फैसले से तय होगा, लेकिन शराब घोटाले से बनीं परिस्थितियों का दबाव उन पर भी है। बेशक जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति उज्जवल भुईयां ने सीबीआई पर तल्ख टिप्पणियां भी कीं, जिसने ईडी केस में जमानत मिलते ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तत्परता दिखाई थी, लेकिन जमानत की शर्तों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की वैसी भूमिका निभा ही नहीं सकते, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। वह न तो नीतिगत फैसले ले सकते हैं और न ही लोक-लुभावन घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। फिर वह चौथी बार जनादेश के लिए मतदाताओं के बीच किस आधार पर जाते? दूसरी ओर जमानत पर रिहा अभियुक्त करार देते हुए भाजपा उनके विरुद्ध चुनाव अभियान चलाती, जिसकी सफाई देते हुए खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताने में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार निकल जाता। लोकपाल के मुद्दे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन का समय हो या उसके बाद बनीं आम आदमी पार्टी की राजनीति का दौर—केजरीवाल की छवि आक्रामक नेता और वक्ता की रही है। ऐसे में अपने और पार्टी के भविष्य की लड़ाई वह रक्षात्मक मुद्रा में लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। पहले भी केजरीवाल सरकार चलाने की जिम्मेदारी अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप कर आप के राजनीतिक विस्तार के जरिये अपनी महत्वाकांक्षाओं के पंख फैलाने में ही जुटे थे इसलिए इस अभूतपूर्व संकटकाल में उन्होंने पद-मुक्त हो कर अपनी उसी पुरानी आक्रामक छवि में लौटने का विकल्प चुना है, जिसने नई नवेली आप को साल भर में ही दिल्ली में सत्तारूढ़ और एक दशक में ही राष्ट्रीय दल बनवा दिया। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आप ने प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे कर केजरीवाल, राजनीतिक प्रतिशोध की शिकार आप के संयोजक के रूप में खासकर भाजपा के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएंगे। अभियान हरियाणा विधानसभा चुनाव से शुरू हो कर दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड तक जारी रहेगा। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत न मिलने से तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी पर बढ़ गई नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता के मद्देनजर इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का महत्व जगजाहिर है। अगर जनादेश भाजपा के अनुकूल नहीं आया तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के तेवर और भी आक्रामक हो जाएंगे। नई लोकसभा के अभी तक के दो सत्रों में और संसद के बाहर भी विपक्ष के तेवर सत्तापक्ष को लगातार घेरनेवाले नजर आ रहे हैं। पूछा जा सकता है कि इन राज्यों में दिल्ली के अलावा तो कहीं भी आप का जनाधार नहीं है। बेशक, लेकिन हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है। लोकसभा चुनाव साथ लड़नेवाली कांग्रेस ने कई दौर की बातचीत के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की तरह आप भी 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के आक्रामक प्रचार का खतरा कांग्रेस आलाकमान समझता है। ऐसे में अभी भी हरियाणा में तालमेल का रास्ता खोजा जा सकता है। विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकनेवाले केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप के लिए कुछ सीटों का दबाव बना सकते हैं।

मोदी सरकार की सौ दिन की उपलब्धियां भी कम नहीं

उमेश चतुर्वेदी

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार के लिए सौ दिनों का समय बहुत ज्यादा नहीं होता। हां, अगर शपथ ग्रहण से पहले भी उसी दल और नेतृत्व की सरकार हो तो सौ दिन के कार्यकाल में बहुत कुछ किया जा सकता है। इन अर्थों में देखें तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के खाते में कई उपलब्धियों का बोलबाला है। मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियों का खुद भी एक लेखा-जोखा पेश किया है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों तरह की कामयाबी शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल के नवंबर महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए चार जातियों का उल्लेख किया था। उनकी नजर में अब चार जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान हैं, जिन पर उनका पूरा ध्यान है। कहना न होगा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इन चारों जातियों को लेकर तमाम योजनाएं बनाई और शुरू की गई हैं। वहीं बुनियादी ढांचा के विकास, पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों को लेकर भी कई योजनाएं मंजूर की गई हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले सौ दिन के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को सुधारने, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं।

जहां तक बुनियादी ढांचे के विकास की बात है तो मोदी सरकार ने अपने पहले सौ दिन के कार्यकाल में सड़क विकास, रेल मार्ग, हवाई सेवा और बंदरगाह के विकास को लेकर तीन लाख करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी है। इस दौरान आठ हाई स्पीड कारीडोर बनाने की मंजूरी दी गई है। जाहिर है कि अगर ये योजनाएं जमीनी हकीकत बनीं तो जहां लाखों नए रोजगार का सृजन होगा, वहीं कारोबार को नई गति मिलेगी और किसानों को उनकी उपज के बाजार तक सीधी और तीव्र पहुंच मिलने का योग बनेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही देशभर के पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि की उन्नीसवी किश्त जारी की गई, जिसके तहत नौ लाख तीस हजार किसानों के खाते में बीस हजार करोड़ की रकम सीधे पहुंचाई गई है।

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में पर्यावरण केंद्रित ऊर्जा संरक्षण और उत्पादन की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश के पूर्वोत्तर इलाके में 41 सौ करोड़ की लागत से पनबिजली, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की योजनाएं मंजूर की हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चालू किया गया है।

मोदी सरकार का दावा है कि उसने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में मध्यम वर्ग को भी बहुत राहत दी है। अब सात लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लेने का फैसला किया गया है। वहीं मानक कर कटौती की सीमा 75 हजार कर दी गई है। जबकि पारिवारिक पेंशन की छूट का दायरा 25 हजार किया गया है। हालांकि इसका फायदा अगले वित्त वर्ष से ही मिल सकेगा। वैसे यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि मध्य वर्ग ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कर छूट में और वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठा था। मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते खाद्यान्न और सब्जियों की महंगाई ने मध्यम वर्ग पर नया बोझ भी बढ़ाया है। जिसकी तरफ अभी सरकारी तंत्र का ध्यान नजर नहीं आ रहा।

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी कारोबार को सहज एवं आसान बनाने की दिशा में भी बड़ी पहल की है। देश में विदेशी निवेश बढ़ सके, इस दिशा में सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स को चालीस प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक हजार करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान भी किया गया है। मोदी सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की ओर भी ध्यान दिया है। इसके तहत 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू किया गया है। इसी दिन पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का मिशन सफल हुआ था। इसके साथ ही गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है।

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन में महिलाओं के लिए जहां दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत दस करोड़ महिलाओं को संगठित करके 90 लाख स्वयंसहायता समूह बनाने का लक्ष्य पूरा किया है, वहीं 11 लाख नई लखपति दीदियों प्रमाण पत्र दिया है। मोदी सरकार ने इस अवधि में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में सुधार को लेकर भी कदम उठाए हैं। आदिवासी समुदाय के लिए जारी नमस्ते योजना का विस्तार किया गया है। वहीं साठ साल से अधिक उम्र वाले दिव्यांग लोगों को एक लाख 17 हजार नए दिव्यांग कार्ड दिए गए हैं।

भारत युवाओं का देश है। उनमें बेरोजगारी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में दो लाख करोड़ के प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान किया है, जिसका इस्तेमाल रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही कौशल विकास में किया जा रहा है। इसके साथ ही एक करोड़ युवाओं को देश की प्रमुख कंपनियों में एक साल के लिए इंटर्नशिप का अवसर भी दिया जा रहा है। युवाओं और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए 'खेलो इंडिया' के तहत नई योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही कर्मचारी प्रोविडेंड फंड संगठन की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है।

भारत इतना विशाल है कि कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन तो कहीं भूकंप तो कहीं तूफान आदि आपदाएं आती रहती हैं। इस दिशा में काम करते हुए मोदी सरकार ने 2005 के आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है, जिस पर संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सहज बनाने की दिशा में भी इस अवधि में काम किया है। जिसके तहत साढ़े चार करोड़ परिवारों को छह करोड़ उन नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है, जिनकी आयु सत्तर वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 75 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उत्तर पूर्व के आतंकी संगठनों एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया है। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांच साल में पांच हजार साइबर सुरक्षा कमांडो तैनात करने का भी फैसला लिया गया है। हालांकि सुरक्षा के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए मणिपुर अब भी चिंता की वजह बना हुआ है, जहां अभी तक शांति नहीं ला जा सकी है। रह-रहकर वहां हिंसा भड़क रही है। कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता समेत तीन कानून देशभर में एक साथ एक जुलाई से लागू किए जा चुके हैं। तीसरे कार्यकाल के सौ दिनों की अवधि में विदेश नीति के मोर्चे पर भारत सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां यूक्रेन और रूस डूदोनों ही देशों की यात्रा की, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने फिजी व तिमोर का दौरा किया। फिजी अब अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए भारत की तरफ देख रहा है। मोदी ने खनिज तेल से समृद्ध देश ब्रूनई का दौरा किया, जिसे भारत की ऊर्जा जरूरतों के संदर्भ में बेहतर कूटनीतिक कदम माना गया है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रमाण-संग्रहाध्यायः (दूसरा अध्याय)

पञ्चदशी

सपुराणान्पञ्च वेदान, शास्त्राणि विविधानि च।
ज्ञात्वाप्यनात्मवित्तेन नारदोऽतिशुशोच ह ।

अर्थात् - नारद जी ऋग्वेद आदि चारों वेदों, और पुराण नामक पाँचवें वेद को तथा अनेक शास्त्रों को जानकर भी आत्मज्ञान बिना अति शोकग्रस्त हुए ।

यह अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त का वही अद्वितीय ग्रन्थ है कि जिसकी अर्थसङ्गति लगाने में प्रतिशत निन्यानवे समाजो मूकप्रायः हो जाते हैं।

शांकर शारीरिक भाष्य

वेदों के विशेषज्ञ श्री कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्र वार्तिक नामक ग्रन्थ में जो पुराणों के प्रामाण्य विषय पर विचार किया है, उसकी समालोचना करते हुये श्री आद्यशङ्कराचार्य लिखते हैं-

इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन्मन्त्रार्थवादमूलत्वात् प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम् ।। (उत्तर मीमांसा)

अर्थात् - इतिहास और पुराणों का मूल भी व्याख्या मार्ग के अनुसार सम्भावित श्रुत्युक्त अर्थवाद है इसलिए वह (इतिहास और पुराण) भी देवताओं के विग्रह आदि की सिद्धि में समर्थ प्रमाण माने जा सकते हैं ।

तस्मात्समूलमितिहासपुराणम् ।।
(उत्तर मीमांसा 6।13।33)

अर्थात् - पूर्वोक्त कारण से इतिहास और पुराण भी वेदमूलक हैं ।

सायणीय कृष्णायजुर्माण्योपोद्घात

उपनीतस्यैवाध्ययनाधिकारम् .....।
कथं हि तयोः-पुराणादिभिरिति ब्रुमः ।
(सायण भाष्य पृ0 3)

अर्थात् - उपनीत के लिये ही वेदाध्ययन के अधिकार को कहा है। तो फिर स्त्री शूद्रों का कल्याण कैसे होगा ? पुराणादि के द्वारा, ऐसा कहेंगे ।

(क्रमशः)

विश्व बांस दिवस

श्वेता

18 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बांस दिवस, एक वैश्विक पहल है जो बांस के अविश्वसनीय महत्व पर प्रकाश डालती है। यह उल्लेखनीय पौधा, जिसे अक्सर ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण में अपार क्षमता रखता है। विश्व बांस दिवस बांस के असंख्य लाभों और वैश्विक चुनौतियों को दूर करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

बांस, तेजी से बढ़ती घास का प्रकार, अपने असाधारण गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ताकत, लचीलापन और पर्यावरण-मित्रता शामिल है। यह दिन एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बांस की अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा और स्थिरता का जश्न मनाता है।

विश्व बांस दिवस विश्व बांस संगठन (डब्ल्यूबीओ) के समर्पित प्रयासों के लिए अपने अस्तित्व का श्रेय देता है, जो 2005 में सुज़ैन लुकास और डेविड नाइट्स द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है। उनका दृष्टिकोण बांस को उद्योगों और आजीविका को बदलने की क्षमता के साथ एक बहुमुखी और मूल्यवान संसाधन के रूप में बढ़ावा देना था।

2009 में, डब्ल्यूबीओ ने बैंकॉक, थाईलैंड में पहली बार विश्व बांस कांग्रेस का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक घटना ने दुनिया भर के बांस के प्रति उत्साही, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग के पेशेवरों को एक साथ लाया।

18 सितंबर 2009 को, 8 वीं विश्व बांस कांग्रेस के दौरान, प्रतिभागियों ने आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया। इस तारीख को प्रसिद्ध बांस शोधकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था। डॉ. कलाम गरीबी और पर्यावरणीय क्षरण का मुकाबला करने के लिए बांस की क्षमता के कट्टर समर्थक थे। इस घोषणा के बाद, विश्व बांस दिवस ने दुनिया भर में बांस संगठनों, पर्यावरण समूहों, सरकारों और बांस के प्रति उत्साही लोगों से मान्यता और समर्थन प्राप्त किया। यह दिन बांस के स्थायी और बहुमुखी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था।

विश्व बांस दिवस बांस की पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति को रेखांकित करता है। बांस की तेजी से वृद्धि, न्यूनतम पानी और कीटनाशक की आवश्यकताएं, और पौधे की जड़ प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना इसे काटने की क्षमता इसे पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार विकल्प बनाती है। यह पालन बांस के विविध उपयोगों पर प्रकाश डालता है, जिसमें निर्माण और फर्नीचर बनाने से लेकर वस्त्र और पाक अनुप्रयोग शामिल हैं। बांस की अनुकूलनशीलता इसे विभिन्न उद्योगों में एक प्रमुख घटक बनाती है। अंत में, यह दिन जिम्मेदार बांस की खेती और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

दोबारा कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, अपनी बात से क्यों मुकरे केजरीवाल ?

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए जनता से ''ईमानदारी का प्रमाणपत्र'' मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लिया है। यदि उनके इस संकल्प को राजनीतिक आधार पर देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन अगर केजरीवाल के इस संकल्प को नैतिकता के आधार पर देखें तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यही है कि जब सरकार का कार्यकाल छह महीने से भी कम का बचा है तब इस्तीफा देने का ऐलान क्यों किया गया? सवाल यह है कि जेल से छह महीने तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड केजरीवाल ने क्यों बनाया? केजरीवाल ने इस साल मार्च में तभी इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा था? केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली सरकार को अदालत की फटकारों के बाद ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? केजरीवाल को यदि अपनी ईमानदारी पर जनता की मुहर ही लगवानी थी तो उन्होंने ईडी की ओर से पूछताछ के लिए भेजे गये पहले समन में ही अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराई थी? क्यों केजरीवाल ने ईडी के आठ समनों की अनदेखी की थी? संविधान और कानून को सर्वोपरि मानने की बात कहने वाले केजरीवाल ने क्यों ईडी के बुलावे को गंभीरता से नहीं लिया था? लोकसभा चुनावों के दौरान जब जनता ने आम आदमी पार्टी के जेल का जवाब वोट से अभियान को खारिज कर दिया तभी केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? केजरीवाल ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया था जब गर्मियों के दौरान दिल्ली की जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही थी? केजरीवाल ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया था जब दिल्ली में बारिश का पानी भर जाने से छात्रों की कोचिंग सेंटर में डूब कर या सड़क पर चलते हुए करंट लग कर मौत हो रही थी? सवाल यह भी उठता है कि मनीष

सिसोदिया के जेल जाते ही उनसे इस्तीफा लेने वाले केजरीवाल ने वही नीति अपने लिये क्यों नहीं अपनाई थी?

सवाल यह भी है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन चलाने वाले और जन लोकपाल के लिए आंदोलन चलाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में जन लोकपाल क्यों नहीं बनाया? सवाल यह भी है कि राजनीति में आने से पहले शराब के ठेकों का विरोध करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के ठेकों की संख्या बढ़ाने और दारू की एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री देने का अभियान क्यों चलाया? सवाल यह भी है कि राजनीति में आने से पहले दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचारी बता कर उनके इस्तीफे की मांग करने वाले केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद एक एक कर सारे घोटालेबाज नेताओं से हाथ क्यों मिलाया? सवाल यह भी है कि राजनीति बदलने का सपना दिखाकर दिल्ली की जनता का वोट लेने वाले केजरीवाल ने बदलाव को खुद पर ही क्यों आजमाया? सवाल यह भी है कि सरकारी घर नहीं लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने लिये सरकारी खर्चे पर शीश महल क्यों बनवाया? सवाल यह भी है कि सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा में दिल्ली और पंजाब पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में क्यों लगवाया? सवाल यह भी है कि सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने लिये आलीशान गाड़ियों का काफिला क्यों तैयार करवाया? सवाल यह भी है कि अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते ही इस्तीफा ले लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और अमानतुल्ला खान जैसे विधायकों पर तमाम आरोपों के बावजूद उनका इस्तीफा क्यों नहीं करवाया?

सवाल यह भी है कि 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की जनता से फिर कभी इस्तीफा देकर भागूंगा नहीं कहने वाले केजरीवाल ने अपना वादा क्यों तोड़ा? हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली में 49 दिन की पहली सरकार चलाने के बाद जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब उन्होंने सोचा था कि 2014 के लोकसभा चुनावों में जनता उनको समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना देगी। इसीलिए वह वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुँच गये थे लेकिन जनता ने वाराणसी और देश के अन्य भागों में उनकी उम्मीदों पर बुरी तरह पानी फेर दिया था। इसके बाद दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले को अपनी गलती मानते हुए जनता से माफी मांगी थी और आगे से ऐसा नहीं करने को कहा था। लेकिन केजरीवाल ने फिर से ऐसा कर दिया है तो सवाल उठता है कि जनता उनकी बात पर भरोसा क्यों करे? वैसे देखा जाये तो केजरीवाल ने भरोसा सिर्फ जनता का तोड़ा हो ऐसा नहीं है। उन्होंने हर चुनाव में यमुना मैय्या से वादा किया कि अगले चुनावों से पहले नदी को पूरी तरह साफ करा दूंगा। लेकिन वादा तोड़ दिया।

केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनवा दो मैं दिल्ली में हर साल सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को खत्म करवा दूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गयी मगर दिल्ली में प्रदूषण कम या खत्म होने की बजाय बढ़ गया। केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध का फैसला किया मगर केजरीवाल के जेल से छूटते ही पटाखे चलाकर अपनी ही सरकार के फैसले का मखौल उड़ाया। केजरीवाल दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति का ढोल हर जगह पीटते हैं लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 11 साल के शासन में कितने नये स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनवाये हैं? केजरीवाल खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पार्टी पर खालिस्तान समर्थकों से चंदा लेने के जो आरोप हैं उसकी सच्चाई क्या है? केजरीवाल कहते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जाता है लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के अब तक के शासन में दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों को निलंबित करने का रिकॉर्ड क्यों बनाया गया?

बहरहाल, एक समय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आंदोलन करते रहे केजरीवाल राजनेता बनने के बाद भी अपने अंदर के आंदोलनकारी को जिंदा रखे हुए हैं इसलिए हर बात पर उनका उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से झगड़ा होता रहता है। जबकि दिल्ली में पूर्व की सरकारों के दौरान मुख्यमंत्रियों का कभी भी उपराज्यपाल या केंद्र से इस तरह का टकराव नहीं रहा। इस तरह का टकराव दिल्ली में तब भी नहीं दिखता था जब राज्य और केंद्र में अलग पार्टियों की सरकारें थीं। मगर केजरीवाल पहले नजीब जंग से लड़ते रहे, फिर वह अनिल बैजल से भिड़े और अब उनका संग्राम उपराज्यपाल वीके सक्सेना से होता रहता है। इस उदाहरण से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामी उपराज्यपाल के स्तर पर है या मुख्यमंत्री के स्तर पर। खैर... केजरीवाल प्रकरण से एक बात तो स्पष्ट है कि एक समय पर नेता और एक्टिविस्ट की भूमिका निभाना दोनों भूमिकाओं के साथ अन्याय करने जैसा है।

आज का इतिहास

1889 हॉल हाउस , संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रभावशाली घर, शिकागो में खोला गया।
1895 डैनियल डेविड पामर ने पहली चिरोप्रैक्टिक समायोजन टोडीफ़े चौकीदार हार्वे लिलार्ड को दिया।
1910 चिली शहर ने स्पेन से आजाद होने के बाद, अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी का जश्न मनाया।
1918 प्रथम विश्व युद्ध- डोब्रो पोल की लड़ाई में सेंट्रल पावर्स की हार ने युद्ध से बल्गेरियाई वापसी में एक भूमिका निभाई और वर्दार मैसेडोनिया के बाद के मुक्ति के लिए रास्ता खोला।
1919 हालैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।
1922 हंगरी लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ।
1926 अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत हुई।
1939 नाजी प्रचार रेडियो कार्यक्रम जर्मनी कॉलिंग, एकहोस्ट उपनाम-लॉर्ड हा-हव 'के साथ, द किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में दर्शकों के लिए प्रसारण शुरू किया।
1942 अमेरिका की पनडुब्बियां प्रशांत महासागर में वर्चस्व की लड़ाई जीत रही हैं। कल उन्होंने 4 और जापानी जहाजों को डुबो दिया और एक और 4 जापानी जहाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया,
1947 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, संयुक्त राज्य वायु सेना को अमेरिकी सेना की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया गया, साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी के रूप में भी।
1955 यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से रॉकॉल के निर्जन द्वीप को एकजुट किया।
1961 तत्कालीन सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया।
1967 नागालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया।
1973 भविष्य के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एरियल फेनोमेना (एनआईसीएपी) पर राष्ट्रीय जांच समिति के साथ एक रिपोर्ट दायर की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अक्टूबर में एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (यूएफओ) देखा था।
1974 हरिकेन फ़िफी ने होंडुरास पर हमला किया, पहले 24 घंटों में 182 कस्बों को नष्ट कर दिया, और अंततः 8,000 से अधिक इलाकों का निर्माण किया।
1988 बर्मा ने अपना संविधान रद्द किया।
1997 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'होलोग' नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
2003 ढाका-अगरतला के बीच बस सेवा शुरू हुई।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा देश

स्वामी चिदानन्द सरस्वती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का शासन संभाले 10 वर्ष पूरे चुके हैं। इस दौरान हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में हुए कार्यों ने देश की सांस्कृतिक विविधता और महान सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित तो किया ही है, साथ ही इसे पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित भी किया है।

नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। बीते 10 वर्षों में देश की राजनीतिक संस्कृति में तो बदलाव आया ही है, कार्यसंस्कृति में बदलाव का भी सबने अनुभव किया है। महान संस्कृति और विरासत के प्रति भी लोगों में भाव जागा है जो आजादी के बाद और मोदी सरकार के आने के पहले कहीं खो गया था।

आज जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। आजादी के बाद से देश में राजनीति के केंद्र रहे राम मंदिर, तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और नागरिकता कानून जैसे तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री ने स्थायी समाधान तक पहुंचाया। मोदी सरकार ने बीते एक दशक में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, गरीब कल्याण और वैश्विक सम्मान का नया कीर्तिमान बनाया है।

पहले देश की सांस्कृतिक विरासत पर कई आघात हुए। देश के विभाजन के बाद न केवल हिंदू समाज को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी बल्कि हमारी महान संस्कृति को भी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वह माहौल बदला। उन्होंने देशवासियों को सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहरों पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को आम जीवन, विदेश नीति और विकास से जोड़ा, जो देश को न केवल एकसूत्र में पिरोता है बल्कि समाज के सभी वर्गों में समानता का सेतु भी बनाता है। काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम के माध्यम से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सांस्कृतिक विविधता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में कितनी कारगर साबित हो सकती है।

बीते वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, उज्जैन में भव्य श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण, अयोध्या में लाखों दीपों से प्रभु श्रीराम की विजय यात्रा का अभिनंदन, 500 वर्ष बाद भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य, जम्मू-कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार, पावागढ़ में भव्य मंदिर का निर्माण, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण, बुद्ध सर्किट का निर्माण, जैन सर्किट का निर्माण, सूफी सर्किट का निर्माण और केदारनाथ-बदरीनाथ-सोमनाथ धाम का विकास इसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है।

1600 वर्ष पुरानी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान हुआ तो योग एवं आयुर्वेद का भी परचम लहराया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने योग को संपूर्ण विश्व के सामने

प्रखरता से रखते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता दिलवाई, यह वैश्विक पटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक स्वीकार्यता का पहला महत्वपूर्ण अवसर था।

जम्मू-कश्मीर के एक बड़े कालखंड के अंतराल के बाद सैकड़ों मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। श्रीनगर में 700 साल पुराने मंगलेश्वर भैरव मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन हो चुका है।

यह एक विडंबना ही थी कि आजादी के वर्षों बाद भी हम उपनिवेशवादी मानसिकता को ढो रहे थे। कई शहरों, सड़कों, कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और यहां तक कि देश की शिक्षा प्रणाली पर भी उपनिवेशवाद की छाप थी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का प्रण लेते हुए इस पर कार्य शुरू किया। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली जिस सड़क का नाम किंग्सवे रखा था, उसे बदलकर उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया। भारतीय नौसेना के ध्वज से भी औपनिवेशिक काल के सेंट जॉर्ज क्रॉस को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से प्रेरित प्रतीक से बदला गया, इसी तरह इंडिया गेट से करीब 150 मीटर पर मौजूद कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जहां पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। इस सबसे आगे बढ़ कर प्रधानमंत्री आवास रेस कोर्स रोड को बदल कर लोक कल्याण मार्ग का नाम दिया गया। ये केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि भाव का परिवर्तन था।

मोदी सरकार ने देश को भारतीयता के विचार से ओत-प्रोत नया संसद भवन दिया, जिसमें भारत की महान सभ्यता की विरासत के अंश के तौर पर सेंगोल को स्थापित किया गया। मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश करते हुए भाषाओं के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। कोई भी युवा भाषाई जटिलता के कारण तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे इसका विशेष ध्यान रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत कई राज्यों मे इंजिनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी भाषा में प्रारंभ की जा चुकी है।

भारत से अंग्रेजों के जाने के 70 वर्षों बाद भी उनके बनाए गए कानून न्यायालयों में बरकरार रहे। ऐसे कई कानून ब्रिटिश राज में भारतीयों के शोषण के औजार थे। गुलामी के हर प्रतीक को समाप्त करने की दिशा में इस सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के रूप में देश को स्वदेशी कानून दिए हैं, जिनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि अपराध रोकना है।

आजादी के अमृत काल में सरकार के इन प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिल रही है। आज देश का युवा अपनी भाषा, संस्कृति और महान विरासत पर गर्व कर रहा है। देश के सांस्कृतिक जागरण के इस महायज्ञ के अग्रदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत के साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

आतिशी अब केजरीवाल की सीएम वाली कुर्सी संभालेंगी

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव स्वयं अरविंद केजरीवाल ने रखा जिसका सभी ने समर्थन किया। वैसे आतिशी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि इससे पहले भी उनका नाम इस पद के लिए सामने आया था। हम आपको याद दिला दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के लिए केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल के समक्ष भेजा था। हालांकि तकनीकी कारणों से आतिशी की बजाय राज्य सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराया था। हम आपको बता दें कि आतिशी विधायक बनने से पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार के तौर पर काम करती थीं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव पूर्वी दिल्ली से लड़ा था लेकिन भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर से हार गयी थीं। उसके बाद वह 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र से विधायक बनीं। पिछले साल जब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल गये तो आतिशी को राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। उस समय मनीष सिसोदिया 18 विभाग संभाल रहे थे। वह सभी 18 विभाग और सिसोदिया का उपमुख्यमंत्री वाला बंगला आतिशी को आवंटित किया गया था। मंत्री के रूप में आतिशी काफी सक्रिय रहीं साथ ही पार्टी का पक्ष भी विभिन्न मंचों पर प्रखरता से रखती रहीं। हालांकि दिल्ली की जल मंत्री के रूप में वह विफल रहीं। अब जब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं तब उन्होंने अपनी कुर्सी भी आतिशी को सौंप कर जता दिया है कि वह हाईकमान की सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद नेता हैं। हम आपको यह भी बता दें कि साल 1998 में दिल्ली में भाजपा ने भी ऐसा ही प्रयोग किया था। तब भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को हटा कर सुषमा स्वराज को विधानसभा चुनावों से तीन महीने पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। सुषमा स्वराज ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनते ही धुआंधार पारी खेलनी शुरू की थी और जनहित में कई बड़े फैसले किये थे मगर वह अपनी पार्टी को सत्ता में वापस नहीं ला सकीं थीं। बल्कि 1998 में अपनी सरकार जाने के बाद से भाजपा दिल्ली की सत्ता में आज तक नहीं लौटी है। बहरहाल, देखना होगा कि भाजपा की तरह चुनावों से तीन महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला आम आदमी पार्टी के हित में रहता है या नहीं?

राहुल गांधी की आरक्षण खत्म करने पर की गई टिप्पणी

अनुप प्रजापति

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में हाल ही में एक बातचीत के दौरान आरक्षण पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया। भारत में आरक्षण के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम आरक्षण को खत्म करने के बारे में तब सोचेंगे जब भारत एक उचित स्थान होगा और भारत एक उचित स्थान नहीं है। इस टिप्पणी ने न केवल सकारात्मक कार्रवाई के प्रति कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में, बल्कि भारत की सामाजिक व्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभाव के बारे में भी व्यापक बहस छेड़ दी है।

आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के साथ कांग्रेस का एक जटिल रिश्ता रहा है। हालाँकि, कांग्रेस ने कई मौकों खुद को हाशिए पर रहने वाले समूहों के चैंपियन के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इतिहास की बारीकी से जांच करने पर अधिक जटिल कथा का पता चलता है। कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व्यापक सकारात्मक कार्रवाई लागू करने में झिझक रहे थे। उसके इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण आरक्षण नीतियों के विरोध से भरा रहा है। राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादास्पद टिप्पणी की, यहां तक कि ओबीसी को बुद्धू (मूर्ख) भी कहा, जिससे पिछड़े समुदायों में आक्रोश फैल गया था। कांग्रेस पार्टी को इस ऐतिहासिक विरोध ने परेशान करना जारी रखा है। जिससे एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति) और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को सही मायने में सशक्त बनाने की उसकी प्रतिबद्धता पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा की गईं टिप्पणियाँ इसी तरह की सोच का संकेत देती हैं, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि मौका मिलने पर कांग्रेस आरक्षण नीतियों को खत्म करने या कमजोर करने को तैयार हो सकती है।

भारत एक कई वर्गों को समुदायों में बंटा समाज है जिसमें जाति, वर्ग और धर्म की जटिल परतें सामाजिक गतिशीलता को आकार देती हैं। देश में दशकों के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के बावजूद, जाति-आधारित असमानता एक कठोर वास्तविकता बनी हुई है। एससी-एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण के रूप में सकारात्मक कार्रवाई ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान करने, समान अवसर प्रदान करने के भारत के प्रयासों की आधारशिला रही है। देश में आरक्षण की आवश्यकता आज भी उतनी ही तीव्र है जितनी तब थी जब इसे पहली बार लागू किया गया था। भारत एक उचित स्थान बनने से बहुत दूर है जहां केवल योग्यता ही सामाजिक गतिशीलता को आगे बढ़ा सकती है। जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित भेदभाव लाखों लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच को सीमित कर रहा है। ऐसे में सकारात्मक कार्रवाई केवल सशक्तिकरण का एक उपकरण नहीं है बल्कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए एक नैतिक आवश्यकता है। भाजपा सरकार समानता लाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं पेश कर रही है।

कांग्रेस के आलोचकों का तर्क है कि राहुल गांधी की टिप्पणियां सकारात्मक कार्रवाई को कमजोर करने के लंबे समय से चले आ रहे एजेंडे के अनुरूप हैं। न्यायिक निर्णयों को उलटने और ऐसी नीतियों को पेश करने में कांग्रेस की भूमिका की ओर कई लोग इशारा करते हैं। जो कई बार अल्पसंख्यक समूहों के पक्ष में एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान पहुंचाती रही हैं। दिसंबर 2005 में पेश किए गए कांग्रेस के 93वें संशोधन ने अल्पसंख्यक संस्थानों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण का पालन करने से छूट दे दी थी। उस समय कई लोगों ने इस कदम को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों पर अल्पसंख्यकों का पक्ष लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा था।

इसके अलावा भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में कांग्रेस द्वारा आरक्षण से निपटने के तरीके ने एससी, एसटी और ओबीसी को और भी अलग-थलग कर दिया, क्योंकि पार्टी समावेशी सकारात्मक कार्रवाई पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को प्राथमिकता देती दिख रही थी। कांग्रेस की आलोचना इस विश्वास तक फैली हुई है कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी आरक्षण को अल्पसंख्यक वोटों, विशेषकर मुसलमानों को एकजुट करते हुए हिंदू समुदायों को विभाजित करने के एक उपकरण के रूप में देखती है। पार्टी के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियाँ चाहे जानबूझकर हों या नहीं, भारत में सकारात्मक कार्रवाई के भविष्य के बारे में बड़ी चर्चा का द्वार खोलती हैं। यदि कांग्रेस पार्टी वास्तव में भविष्य में आरक्षण खत्म करने पर विचार कर रही है, तो यह भारत के सामाजिक ताने-बाने पर संभावित असर के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। क्या भारत जैसा विविधतापूर्ण और ऐतिहासिक रूप से असमान देश समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अपने प्रमुख उपकरणों में से एक को ख़त्म करने का जोखिम उठा सकता है?

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यह टिप्पणी कि भारत एक उचित स्थान नहीं है अनजाने में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हालाँकि, निष्पक्षता प्राप्त होने के बाद आरक्षण ख़त्म करने की धारणा समस्याग्रस्त है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में निष्पक्षता को एक स्थिर लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है जिसे एक निश्चित समय सीमा में हासिल किया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें गहरी बैठी असमानताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। भारत के लिए, निष्पक्षता का मार्ग लंबा और जटिल है, और सकारात्मक कार्रवाई यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। समय से पहले आरक्षण ख़त्म करने से दशकों की प्रगति उलट सकती है, जिससे सबसे कमज़ोर लोग और भी पीछे रह जाएंगे।

शराब नीति मामले में 'ईमानदारी' का बचाव या सियासी चाल?

अजय कुमार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह निर्णय एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जो न केवल उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित करेगा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी नया मोड़ ला सकता है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद, उन्होंने 15 सितम्बर को आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दो दिन बाद वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें फिर से चुनकर भेजेगी। यह निर्णय, हालांकि बहुत से लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात हो सकता है, लेकिन यह उनकी रणनीतिक सोच का एक हिस्सा है। इस कदम के पीछे उनका उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य में अपनी ईमानदारी की छवि को और मजबूत करना और दिल्ली की राजनीति में अपनी स्थिति को पुन: स्थापित करना है।

अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरकर राजनीति में प्रवेश किया था। इस आंदोलन ने उन्हें एक ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में स्थापित किया। आम आदमी पार्टी ने स्वयं को ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक माना है। इस संदर्भ में, दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर विपक्ष, खासकर बीजेपी, ने लगातार पार्टी और केजरीवाल की छवि पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने बार-बार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की थी और आरोप लगाया था कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

हालांकि, केजरीवाल की जमानत के बाद अधिकांश गिरफ्तार किए गए नेताओं को भी जमानत

मिल चुकी है, और आम आदमी पार्टी ने इस पर न केवल अपना पक्ष रखा है, बल्कि यह भी दिखाया है कि शराब नीति मामले में कई मुद्दे हैं। पार्टी इस तरह की स्थितियों को जनता के बीच यह संदेश देने के लिए उपयोग कर रही है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित हो सकता है और नेताओं को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस दृष्टिकोण से, केजरीवाल का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो उनकी पार्टी के नैरेटिव को मजबूत करने का प्रयास है।

केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के फैसले के साथ यह भी कहा है कि उनके पास केवल उनकी ईमानदारी है, और उनके बैंक खाते खाली हैं। उन्होंने यह तर्क किया कि उनका उद्देश्य कभी भी पद और धन के लालच से प्रेरित नहीं रहा। इसके बजाय, उनका प्राथमिक उद्देश्य देश और समाज की सेवा करना है। उनके अनुसार, उनका यह निर्णय जनता के अदालत में अपनी ईमानदारी का परीक्षण कराने का एक तरीका है। वे जनता से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वे उन्हें ईमानदार मानते हैं या गुनहगार।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश के तहत, केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। उनमें से एक यह है कि वह अपने दफ्तर या सचिवालय में नहीं जा सकते और केवल उन फाइलों पर साइन कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना है। इस स्थिति में, केजरीवाल को दिल्ली में अपनी कार्यशैली और प्रशासनिक स्वतंत्रता को लेकर सीमित जगह मिल रही है। इसके चलते, उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है ताकि जल्दी चुनाव कराए जा सकें।

केजरीवाल ने यह भी मांग की है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के बजाय नवंबर 2024 में कराए जाएं। उनका मानना है कि नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव कराने से बीजेपी को इन राज्यों की सियासत में व्यस्त रहना पड़ेगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इस रणनीति का उद्देश्य आम आदमी पार्टी को सियासी लाभ दिलाना है और बीजेपी को अपनी चुनावी योजनाओं पर फिर से विचार करने पर मजबूर करना है।

अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस को भी हैरत में डालने वाला है। खासकर हरियाणा में विधानसभा चुनावों के समय केजरीवाल का इस्तीफा और उनका राजनीतिक सन्देश यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी किसी भी राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए तत्पर है। केजरीवाल के इस्तीफे के साथ-साथ मनीष सिसोदिया ने भी चुनाव तक किसी भी पद को ग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि पार्टी अपनी ईमानदारी की छवि को बनाए रखने के लिए गंभीर है।

इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान, केजरीवाल ने भी कुछ प्रमुख राजनीतिक दांव खेले थे और बीजेपी के नेताओं को सफाई देने के लिए मजबूर किया था। अब, हरियाणा और अन्य राज्यों में चुनाव के साथ, केजरीवाल का यह कदम निश्चित रूप से राजनीतिक पिच पर नया मोड़ ला सकता है। उनके इस्तीफे के साथ, वे दिल्ली की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए तैयार हैं, जिससे यह साबित हो सके कि उनकी पार्टी और वे व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

केजरीवाल के इस्तीफे की परछाई के पीछे निहितार्थ बहुतेरे

डॉ. रमेश ठाकुर

भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का आगमन बहुत अलहदा और अकल्पनीय रहा है। अब एक और नए प्रयोग की ओर अग्रसर हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र 4-5 महीने शेष हैं। इस दरम्यान आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल एक पूर्व मंत्री का भारतीय जनता पार्टी में चले जाना। सैकड़ों कार्यकताओं का मोहभंग होना? उनका टूटकर दूसरे दलों में जाने का सिलसिला शुरू हो जाना। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कमजोर पड़ जाना, इसके अलावा भाजपा का समूची दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रचार-प्रसार करना कि उनके कुर्सी से चिपके रहने की जिद ने राजधानी को दलदल की खाईं में धकेल दिया। भाजपा-कांग्रेस का आप पार्टी पर हमलवर होने जैसे से दिल्ली वासियों में केजरीवाल के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोट का धीरे-धीरे पनपना, जैसे तमाम वैचारिक और राजनैतिक मसलों ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने पर विवश कर दिया। केजरीवाल के निर्णय को दिल्ली के लोग बहुत देरी से लिया गया फैसला बता रहे हैं। हालांकि, उनके इस निर्णय को चुनावी पंडित भाजपा को फंसता हुआ भी बता रहे। वो मानते हैं कि केजरीवाल की जेल, बेल फिर इस्तीफा देने के खेल में भाजपा की तय चुनावी रणनीति फंस गई है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल ने 15 सितम्बर को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही तो सभा में मौजूद सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं-समर्थकों ने हाथ उठाकर 'नहीं-नहीं' बोलने लगे। केजरीवाल ने सार्वजनिक ऐलान करके कह दिया है कि अगले दो दिनों के भीतर वह कुर्सी छोड़ देंगे। इस्तीफे के निर्णय से केजरीवाल समझते हैं कि उनका ये बड़ा सियासी दांव साबित होगा, इससे पार्टी की बीच में गड़बड़ाई स्थिति में सुधार होगा और पिछले तीन चुनावों में उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, वह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा। देश इस बात से वाकिफ है कि पिछले दो चुनाव उनके लिए कश्मिई रहे, जिनमें 70 सीटों में 67 और 62 सीटें जीतकर दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस का मानो पूरी तरह से सफाया ही कर दिया था। लेकिन अब भाजपा की तैयारियां भी अच्छी हैं। आगामी चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये बात खुद केजरीवाल स्वीकारते हैं। दरअसल, केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता दरबार में दोबारा से पहले जैसी सहानुभूति पाना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कह दिया है कि वह अब तभी मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे, जब जनता चाहेगी। मतलब पानी की तरह बिल्कुल साफ है। यानी अगले चुनाव की बिसात उन्होंने बिछा दी हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल तकरीबन समाप्ति की ओर हैं। इसलिए केजरीवाल ने गेंद को जनता के पाले में फेंककर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता अगले चुनाव में गेंद को केजरीवाल की ओर किक करती है या तमतमाई बैठी भाजपा के पाले में गेंद को उछालेगी। केजरीवाल अगर वास्तव में सियासत दांव नहीं खेलते तो वह विधानसभा भंग करके तुरंत चुनाव में भी कूद सकते थे। लेकिन उन्हें ऐसा इसलिए नहीं किया, क्योंकि ये वक्त उनके मुताबिक नहीं है। भाजपा ने अभी उनसे एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीता है। भाजपा के लोग तभी से मैदान में एक्टिव हो गए हैं, जब से केजरीवाल जेल गए थे। दिल्ली को जीतने के लिए भाजपा आगामी चुनाव में किसी भी हद को पार करेगी। क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी ने सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चुनाव जीतने के लिए ललकारा है। संसद से लेकर सार्वजनिक सभाओं में आप पार्टी के नेता कहते हैं कि मोदी-शाह की जोड़ी दिल्ली में कभी भी केजरीवाल को नहीं हरा सकती। सूचनाएं ऐसी हैं कि भाजपा आगामी चुनाव में अपनी फायर ब्रांड नेत्री स्मृति ईरानी को केजरीवाल के मुकाबले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उतारने की तैयारी में हैं। इसके लिए दिल्ली के सातों सांसद को अभी से अंदरखाने चुनावी मैदान में तैयारियों के लिए उतारा हुआ हैं। भाजपा का मुख्य मुद्दा 'दिल्ली शराब घोटाला' ही रहेगा। ये ऐसा मुद्दा है जिसके बूते वो अगला चुनाव जीतने की फिराक में है। लेकिन वहीं, इस मुद्दे की हवा निकालने के लिए केजरीवाल की टीम भी कमर कसकर बैठी है। शराब घोटाले को आम आदमी पार्टी शुरू से फेक बताती आई है। फिलहाल भाजपा नहीं चाहती थी कि केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने प्रचार-प्रसार के कुछ स्लोगन बना रखे थे, जैसे 'दिल्ली का जिद्दी मुख्यमंत्री', 'लालची मुख्यमंत्री' और 'बिना मुख्यमंत्री की दिल्ली' इत्यादि।

संयुक्त परिवार के फायदे

- बड़े परिवार में बच्चे को भरपूर प्यार और स्नेह मिलता है। यही स्नेह, प्यार बच्चे के अन्दर सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। उसके अन्दर संसार को देखने, जानने की उत्सुकता बढ़ती है।
- बच्चे का परिवार में एक अलग स्थान बन जाता है। उसे केवल एक समूह का हिस्सा नहीं माना जाता। हर व्यक्ति उसका खास ध्यान रखता है। इस तरह बच्चा परिवार के हर व्यक्ति का आत्मीय बन जाता है।
- परिवार के साथ रह कर ही बच्चा चीजों को देखना, परखना सीखता है। उसे नई बातें सीखने के अवसर मिलते हैं। वह धीरे-धीरे अपने कामों को समझने लगता है। इतना ही नहीं वह अपनी उम्र के मुताबिक जिम्मेदारी भी उठाना सीखता है।
- बड़े परिवार में हर उम्र के लोग होते हैं। चूंकि बच्चा हर समय देखता और सीखता रहता है, इसलिए हर उम्र के लोगों के साथ रहना, उसके लिए फायदेमंद होता है। उसे परिवार में तरह तरह के लोगों से मिलने, खेलने तथा सीखने के अवसर मिलते हैं।
- बच्चा हर समय और हर जगह सीखता रहता है। इसलिए उसे सिखाने या समझाने का कोई खास समय या स्थान नहीं बनाना चाहिए।
- बच्चा परिवार में कई लोगों से घिरा रहता है, जो उसमें रुचि लेते हैं और जीवन की गाड़ी चलाने में उसके मार्गदर्शक बनते हैं। बच्चा उनके ही व्यवहार से अलग अलग उम्र के लायक बातें सीखता है। साथ ही अनुशासित होना भी सीखता है।
- बच्चा अपने परिवार में बोलचाल की भाषा सुनता है और नकल करके, उसे बोलने की कोशिश करता है। इस प्रकार तरह तरह के प्रयोगों द्वारा परिवार में ही बोली का अभ्यास भी होता रहता है।
- बच्चा नकल करके, देखकर, सुनकर सीखता है। अतः परिवार के साथ रहने पर उसे बहुत कुछ अपने आप ही आ जाता है।
- परिवार में रहने से बच्चे की कल्पना एवं रचना शक्ति बढ़ती है। वह अक्सर दूसरे बच्चों के साथ माता-पिता की नकल करता है। बाबा-दादी बनकर खेलता है। इस तरह वह परिवार, समाज की तरह तरह की भूमिकाएं निभाना सीखता है। उसे परिवार या समाज के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की यह पहली सीढ़ी भी कही जा सकती है।

अवसर दें बच्चों को

परिवार बच्चों को सीखने या आगे बढ़ने के जो अवसर देता है, वह उसे किसी भी जगह नहीं मिल सकती। किसी स्कूल में एक अध्यापक के साथ बच्चों का पूरा समूह होता है। वह हर बच्चे पर पूरा पूरा ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए बच्चे को विकसित होने के लिए परिवार जैसा अच्छा माहौल कहीं नहीं मिल सकता।

बच्चों को ऐसे बढ़ाएं आगे

परिवार हमारे समाज की पहली इकाई है। लेकिन आधुनिकता और भौतिकता की दौड़ में आज परिवार छोटे और छोटे ही होते चले जा रहे हैं। माता-पिता बच्चों को कैसे समझाएं, जिससे बच्चे सदा आगे बढ़ते रहें। आइये जानते हैं इस बारे में।

आने वाले समय में हमारे समाज की इस इकाई का क्या स्वरूप होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसी भी दशा में किसी भी समाज की पहली इकाई परिवार है। दुनिया के हर समाज में परिवार को महत्व दिया गया है। हां इसका स्वरूप अलग अलग जगहों पर अलग तरह का है। परिवार कहीं छोटे तो कहीं बड़े हैं। कहीं पर परिवार में मां, पिता और एक बच्चा ही है। कहीं पर पिता, मां, बच्चों और बाबा दादी को मिलाकर परिवार बना है। सम्मिलित परिवार में सब तरह के रिश्ते और उम्र के लोग होते हैं।

शहरी और ग्रामीण परिवेश

भारत में खासकर गांवों में परिवार बड़े हैं। लेकिन शहरों में परिवार छोटे हैं। शहरों में बच्चे को मां-बाप के साथ छोटे से मकान में रहना पड़ता है। कुछ परिवारों में बच्चा अपने चाचा, चाची, माता-पिता के साथ रहता है, परन्तु इन सभी परिवारों में मां-बच्चे के बीच सबसे अधिक नजदीकी रिश्ता है। बच्चे के विकास में भी मां की ही सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रहती है। बच्चा पैदा होने के बाद से मां के आंचल में रहते हुए भी सीखना शुरू कर देता है। मां की लोरियां उसे सिर्फ सुलाती ही नहीं, उसके अन्दर प्रारंभ से ही सुनने, ध्यान देने और समझने की क्षमता भी विकसित करती है।

संयुक्त परिवार का महत्व

दूसरी ओर माता-पिता या बाबा-दादी, नाना-नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां उसका नैतिक, चारित्रिक विकास करने के साथ ही उसके अंदर मानवीय मूल्यों की नींव भी डालती हैं। इसीलिये मां को पहली शिक्षक भी कहा जाता है।

वातावरण का असर

बच्चे के विकास पर उसके परिवार तथा वातावरण का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कुछ खास बातें ऐसी हैं, जो हर परिवार में पाई जाती हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा परिवार। और इन बातों का असर बच्चे के पूरे व्यक्तित्व, उसके विकास पर सीधे पड़ता है। इन बातों का परिवार के आर्थिक स्तर, गरीबी-अमीरी से कोई मतलब नहीं है।

परेशानी न बन जाएं आपके बच्चे

ऐसा नहीं है कि लड़के शैतान होते हैं। लड़कियां भी कम जिद्दी व शैतान नहीं होतीं। इस तरह की समस्याएं किन्हीं दो-चार महिलाओं की नहीं वरन् अधिकतर महिलाओं को इस दौर से गुजरना पड़ता है। उन्हें हर रोज ही इस तरह की किसी न किसी शर्मनाक स्थिति से दो-चार होना पड़ता है। तो क्या इसी वजह से वे कहीं आना-जाना छोड़ दें, या फिर बच्चे को साथ ही न ले जाएं? तो फिर उसे कहां छोड़ें? कई महिलाओं का यह भी तर्क है कि जब तक बच्चा इस तरह सभा-सोसायटी में जाएगा नहीं तो वह उठने-बैठने के तौर तरीके सीखेगा कैसे?

ये सब तर्क किसी हद तक वाजिब भी हैं, परंतु आपका लाड़ला दूसरों की परेशानी का सबब बन जाए, यह भी तो उचित नहीं है। मां होने के नाते बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आप ही की है।

ऐसे समझाएं बच्चे को

जब तक आपका बच्चा समझदार न हो जाए, आपको ही अपने सुखों का त्याग करना होगा। यह भी ठीक नहीं है कि हर समय आप ही त्याग करें। इसके लिए पति-पत्नी दोनों को मिलकर सहयोग करना होगा। घर में यदि कोई दूसरी महिला जैसे मां, सास-नन्द, जेठानी, देवरानी हो तो बच्चा कुछ समय के लिए उनके पास भी छोड़ा जा सकता है। किसी पार्टी या ऐसी ही कोई पार्टी, जहां केवल महिलाएं ही आती हों, बच्चे को साथ न ले जाएं।

संभल के करें ब्लीच

चेहरे को साफ-सुथरा व कांतिमय बनाने के लिए ब्लीच एक बेहतर विकल्प है। इसे लगाते समय बस, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि यह आंखों के ऊपर लग गया तो बहुत अधिक नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इसे आंखों व आई ब्रो पर नहीं लगाएं।

इन बातों का रखें ख्याल

- त्वचा में अधिक जलन होने पर मिश्रण में क्रीम की मात्रा बढ़ाएं।
- ब्लीच को कभी आंखों, आई ब्रो व सिर के बालों पर न लगने दें।
- हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ही ब्लीच इस्तेमाल करें।
- ब्लीच का अधिक इस्तेमाल आपकी त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकता
- बॉक्स पर दिए गए निर्देशानुसार ही ब्लीच क्रीम में अमोनिया पावडर की मात्रा डालें।
- क्रीम और पावडर के इस मिश्रण को पहले कोहनी पर या अन्य जगह पर लगाकर देखें।

बाल्यावस्था बहुत ही नाजुक तथा मासूम चरण होता है। इसी अवस्था में बच्चों को मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन शहरी महिलाएं अधिक व्यस्तता और दोहरी जिन्दगी के कारण घर परिवार को कम समय दे पाती हैं। फलतः बच्चों को अपने माता-पिता का संरक्षण एवं निर्देशन नही मिल पाता है।

मां की ममता से दूर होता बचपन

मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि परिवार में ही बालक का चरित्र तथा मनोवृत्तियां विकसित होती हैं। परिवार में ही बालक कोमलता, सहानुभूति, आत्मसमर्पण तथा जिम्मेदारी महसूस करना आदि आवश्यक गुण सीखता है। डॉ. सेठी राजनीति शास्त्र की प्रोफसर हैं। श्रीमती सेठ के पति भी नौकरी करते हैं। इनका एक वर्ष का पुत्र शौर्य है, जिसकी देखभाल इनके अलावा आया करती है। आया तथा पति के न रहने के कारण वे शौर्य को कभी-कभी सोते हुए घर पर छोड़कर कॉलेज चली जाती है।

समय का अभाव : सोम्या का कहना है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक पांच साल का तथा दूसरा आठ साल का। जिसकी देखरेख आया करती है। आठ-दस घंटे बच्चे आया के साथ रहते हैं, जिसके कारण इनका आया से ज्यादा लगाव हो गया है। यहां तक कि बच्चे उसी के साथ रहना तथा उसी के हाथों खाना पसंद करते हैं। आया थोड़े दिनों के लिए भी अपने गांव जाती है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक परिवार हैं जो बच्चों को अपने से दूर रखते हैं।

पालन-पोषण पर ध्यान दें : माता-पिता से बालक के संबंध में तादात्म्य ही नहीं बल्कि अनुकरण, संकेत और सहानुभूति की प्रक्रियाएं भी काम करती हैं। माता-पिता जैसा करते हैं, वैसा बालक भी करने लगते हैं। माता-पिता और बालक के संबंधों का व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उनकी उपेक्षा अनुचित है। इससे बालकों में अनेक आपराधिक प्रवृत्तियां बन जाती हैं। बालक अपने बड़ों के अनुकरण से बहुत कुछ सीखते हैं। माता-पिता ही समाज के रीति-रिवाजों, व्यवहारों, संस्कृति के अन्य आवश्यक अंगों, स्वास्थ्य रक्षा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सहयोग आदि की व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। इसलिए बच्चों के सारे कामों में भाग लें। बच्चों को अधिक समय दें। उनकी पढ़ाई खुद देखें। यदि आप काम में लगी हों तो आयु के अनुसार उन्हें भी काम देकर अपने पास बैठाएं। उन्हें एक व्यक्ति मानकर सम्मान दें, बच्चा मानकर न चलें। बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान दें। उनके साथ पारस्परिक सद्भावना, आदर्श, प्रेमपूर्ण रिश्ता कायम करें।

फाउंडेशन मेकअप का बेस, चमकाए फेस

मेकअप बेस के तौर पर फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे चेहरे पर आए कील-मुंहासे, झांइयां तथा दाग-धब्बे छिप जाते हैं। पर इसका सही इफेक्ट तभी आता है, जब यह सही तरीके से लगाया जाए। आइए समझते हैं फाउंडेशन की एबीसीडी

मेकअप बेस के रूप में फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे चेहरे की त्वचा चिकनी और समतल बनती है तथा मेकअप को अधिक देर तक रखने के लिए भी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेकअप का आधार होने के साथ-साथ त्वचा की रक्षा भी करता है और इसके इस्तेमाल से कील-मुंहासे, झांइयां तथा दाग-धब्बे छिप जाते हैं।

फाउंडेशन लगाने का सही तरीका फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे और गर्दन की त्वचा को क्लींजिंग क्रीम या लोशन से साफ करें। उसके बाद रुई की मदद से चेहरे और गर्दन पर फाउंडेशन लगाना चाहिए। या फिर अपने चेहरे के विभिन्न हिस्सों पर फाउंडेशन को डॉट्स की तरह लगाएं। फिर अपनी अंगुलियों या गीले स्पंज से चेहरे पर अंदर से बाहर की ओर हल्के से मसाज करते हुए फाउंडेशन को मिलाएं। तैलीय त्वचा पर फाउंडेशन लगाने से पहले रुई से एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएं। और फिर कुछ देर बाद फाउंडेशन लगाएं। एस्ट्रिजेंट लोशन से त्वचा की चिकनाई दूर होती है। इसी तरह ड्राई स्किन पर फाउंडेशन लगाने से पहले ग्लिसरीन या मॉइश्चराइजर पूरे चेहरे पर लगाना चाहिए। सामान्य त्वचा के लिए कोई भी फाउंडेशन चल सकता है, मगर ऑयली त्वचा के लिए वॉटर बेस्ड और शुष्क त्वचा के लिए मॉइश्चराइजर फाउंडेशन अच्छा होता है। आपकी स्किन ड्राई है, तो फाउंडेशन में दो-तीन बूंद पानी मिलाकर चेहर पर लगाएं। चेहरे पर फाउंडेशनझ अधिक न लगाकर उचित मात्रा में ही लगाएं। फाउंडेशन लगाने के बाद टिश्यू पेपर से उसे इकसार कर लें और थोड़ी देर सूखने दें। उसके बाद उस पर फेस पाउडर लगाएं। रात और दिन के हिसाब से फाउंडेशन का चयन करना उचित होता है। इसमें गोल्ड फाउंडेशन नाइट पार्टी के लिए सही होता है।

फाउंडेशन का चुनाव

फाउंडेशन का मतलब सिर्फ त्वचा के रंग को बदलना ही नहीं होता, बल्कि त्वचा के निकटतम रंग से मैच करना होता है। इसलिए फाउंडेशन का चुनाव अपने चेहरे के रंग के अनुसार ही करें। इनका चुनाव आप अपनी स्किन को ध्यान में रखकर कर सकती हैं। बाजार में फाउंडेशन कई रूपों में उपलब्ध हैं, जैसे लिक्विड, क्रीम, स्टिक, पाउडर फॉर्म में। यदि कोई दुविधा हो, तो ब्यूटी एक्सपर्ट से पूछने में जरा भी न हिचकें। गर्मियों में पैनस्टिक या केक फाउंडेशन हार्ड हो जाते हैं। इस स्थिति में फाउंडेशन लगाने से पहले थोड़ा पानी मिलाएं।

कैसे लगाएं

फाउंडेशन से न सिर्फ चेहरे को आकर्षक बनाया जाता है, बल्कि इससे चेहरे की बनावट में भी बदलाव लाया जा सकता है। मगर यह तभी संभव है, जब आप इसे लगाना जानती हों।

फाउंडेशन सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि गर्दन और कान के हिस्से पर भी एकसार लगाएं।

अगर चेहरा गोल हो, तो उस पर गहरे रंग का फाउंडेशन लगाएं। यदि फेस स्क्वायर या डायमंड शेप है, तो जबड़े और ठोड़ी पर गहरे रंग का फाउंडेशन तथा शेष चेहरे पर उससे हल्के रंग का फाउंडेशन लगाएं।

यदि आंखों के नीचे की त्वचा का रंग हल्का है, तो यहां गहरे रंग का फाउंडेशन लगाना चाहिए। आंखों के नीचे काले निशान या झांइयां होने की स्थिति में वहां हल्के रंग का फाउंडेशन लगाएं।

चौड़ी नाक को पतला दिखाना हो, तो बाकी चेहरे की तुलना में नाक के दोनों ओर गहरे रंग का फाउंडेशन लगाएं। अगर गालों की हड्डियां उभरी हुई हों, तो उसके नीचे गहरे रंग का फाउंडेशन लगाएं।

फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरे पर फेस-पाउडर लगाना चाहिए। पाउडर फाउंडेशन के शेड का अथवा उससे एक शेड हल्का लगाना चाहिए। फाउंडेशन की तरह ही फेस पाउडर अनेक रंगों में उपलब्ध है। इसलिए इसका चुनाव त्वचा के रंग और फाउंडेशन के शेड के अनुसार ही करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी के लिए बीजेपी नेताओं के बयानों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अनुशासन और मर्यादा के जरिए ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। ऐसे बयानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भारत की राजनीति का पतन होने से रोका जा सके। मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने लिखा कि आप अवगत होंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। खड़गे ने आगे लिखा कि मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है, वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर एक आतंकवादी कह रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल से मांगा इस्तीफा

नईदिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है। केजरीवाल के आतिशी को सीएम बनाने के फैसले पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यही कारण है कि अब आप ने स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांग लिया है। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि एक बात समझ लीजिये। स्वाति मालीवाल वो शख्स हैं जो राज्यसभा का टिकट तो आम आदमी पार्टी से लेती हैं लेकिन प्रतिक्रिया देने की स्क्रिप्ट बीजेपी से लेती हैं। दिलीप पांडे ने आगे कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह राज्यसभा में रहना चाहती हैं तो उन्हें बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए। इससे पहले आप सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है।

जनता नक्सली कम्युनिस्ट सीएम स्वीकार नहीं करेगी

नईदिल्ली। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के स्थान पर मंत्री आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री होंगी। इस बीच दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट लिख आतिशी पर हमला बोला है। मिश्रा ने लिखा है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा सीएम चुन रही हैं, जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को उनके स्थान पर अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे 'आप' विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

सेबी चीफ मामले में सीतारमण के बयान पर कांग्रेस का तंज

नईदिल्ली। कांग्रेस ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच के मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया के बाद मंगलवार को कहा कि सेबी प्रमुख और उनके पति के वित्तीय लेन-देन को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, अब तक उनका किसी ने खंडन नहीं किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि क्या वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2022 से ही इन तथ्यों की जानकारी थी? वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा था कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच अपना बचाव कर रहे हैं और ऐसे तथ्य सामने रख रहे हैं जो कांग्रेस के आरोपों के विपरीत हैं। माधवी पुरी बुच और धवल बुच ने अनियमितता बरतने और हितों के टकराव को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि ये आरोप ''झूठे और साख बिगाड़ने'' की कोशिश हैं।

370 पर 5 जजों की बेंच का फैसला पलटवाएंगे उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से धारा 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 को फिर से लागू करना असंभव नहीं है। पांच जजों की बेंच का 370 के खिलाफ फैसले को लेकर अब्दुल्ला ने कहा कि सात जजों की बेंच 370 के पक्ष में फैसला दे देगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कई दिनों से कैंप करता आया हूं। अब पहले फेज का कैंपेन खत्म हुआ और दूसरे चरण का शुरू हुआ। अब इसमें तेजी आएगी। इस दौरान उमर से जब पूछा गया कि धारा 370 का वापस लौटना अमित शाह ने नामुमकिन बताया है। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार 370 के हक में फैसला किया। जब बीजेपी के पास राजीव गांधी के ऐतिहासिक कामयाबी के दौर में 2 सांसद थे। तब नामुमकिन क्यों नहीं था।

केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली के लिए दुखद

चुनाव तक ही रहूंगी मुख्यमंत्री, मुझे बधाई मत दीजिए : आतिशी

नईदिल्ली। दिल्ली आप विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुईं। अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने के बाद वह दिल्ली की नई सीएम होंगी। आतिशी ने कहा कि मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने केजरीवाल को अपना गुरू भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का भी आरोप लगाया।

इस दौरान आतिशी ने कहा कि आज मैं खुश भी हूं और दुखी भी। दुख इसलिए कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर सेवा के लिए राजनीति में आया। उन्होंने कहा कि ऐसे ईमानदार आदमी पर बीजेपी ने झूठे केस किए किए गए। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो नाम है अरविंद केजरीवाल। आतिशी ने कहा कि मैं एक साधारण परिवार से हूं। अगर मैं किसी और पार्टी में होता तो शायद मुझे चुनाव का टिकट भी नहीं मिलता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक और मंत्री बनाया और आज मुझे सीएम की जिम्मेदारी दी।

आतिशी ने कहा कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर इतना भरोसा किया। लेकिन मुझे दुख भी है क्योंकि दिल्ली के सीएम और मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। सभी क्र विधायकों और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से कि दिल्ली का सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है - अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी (आप)के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए दावा करेगी।

आप के विधायक दल की बैठक मंगलवार को केजरीवाल के आवास पर हुई। बैठक में केजरीवाल ने आतिशी को अपनी उत्तराधिकारी चुनने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद आप ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की। आप की दिल्ली इकाई के संयोजक राय ने कहा कि नए मंत्रिमंडल पर फैसला पार्टी बाद में लेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मिलेगा और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा।

आतिशी के सीएम होने पर आप सांसद ने उठाए सवाल

नईदिल्ली। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए सीएम के लिए आतिशी का नाम प्रस्तावित किया। अधिकांश विधायकों ने इस पर सहमति जतायी. जब विधायक दल की बैठक स्थगित हुई और वोटिंग खत्म हुई तो आतिशी के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। हालांकि, आप सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दावा किया कि उनके माता पिता ने आतंकी अफ़ज़ल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाऐं लिखी। उनके हिसाब से अफ़ज़ल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साज़िश के तहत फँसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ़ 'डमी सीएम' है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे! आतिशी को आप विधायक दल का नेता और दिल्ली का नया सीएम चुने जाने के बाद दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज दिल्ली आप विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को अगले दिल्ली चुनाव तक सीएम की जिम्मेदारी दी गई।

भाजपा ने आतिशी को बताया डमी मुख्यमंत्री

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित से सत्ता छीनने के एक दशक बाद दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों की बैठक में अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठ आप नेता और मंत्री आतिशी का नाम प्रस्तावित किया। केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि वह पद से इस्तीफा दे देंगे और तभी लौटेंगे जब लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे। आतिशी के नाम के ऐलान के बाद भाजपा आप पर हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने न चाहते हुए भी उन्हें सीएम बनाया। मनीष सिसोदिया के दबाव के कारण वह अपना मनचाहा सीएम नहीं बना सके। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सारे विभाग भी मनीष सिसोदिया की वजह से ही दिए गए थे। उनके दबाव में आतिशी को सीएम बनाया गया है। चेहरा बदल गया है लेकिन भ्रष्ट चरित्र वैसा ही है और दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आप सरकार उस व्यक्ति का समर्थन करती है जिसके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी रोकने की कोशिश की थी। भंडारी ने कहा कि दिल्ली की जनता कभी भी नक्सली समर्थकों को स्वीकार नहीं करेगी। आप यह दिखाना चाहती है कि वह महिलाओं के साथ डमी और कठपुतली जैसा व्यवहार करती है, जैसा कि सौरभ भारद्वाज कहते रहे हैं कि नया सीएम कठपुतली सीएम होगा।

प्रधानमंत्री ने ओडिशा में कांग्रेस पर बोला हमला

कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इसलिए भड़का क्योंकि मैंने गणेश पूजन में भाग लिया: मोदी

भुवनेश्वर। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में सुभद्रा योजना के उद्घाटन मौके पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए हैं, क्योंकि मैंने गणेश पूजन में भाग लिया था। इस दौरान पीएम ने एक आदिवासी परिवार से भी मुलाकात की।

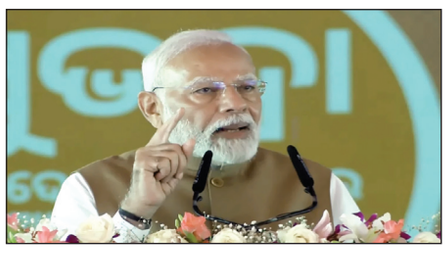

प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश उत्सव हमारे देश के लिए सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो उनका हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिये भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच, नीच, भेद-भाव इन सब से ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है।

पीएम ने कहा कि कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार ने भगवान गणेश की प्रतिमा को सलाखों के पीछे डाल दिया। ऐसी नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता देश के लिए खतरनाक है। ऐसी ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देना है। साथ मिलकर कई मुकाम हासिल करने हैं। देश और ओडिशा को आगे लेकर जाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है, जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। देश में डिजिटल करेंसी से ओडिशा की महिलाएं जुड़ेंगीं। पीएम ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना महिला सशक्तीकरण का प्रतिबिंब है। इस योजना के तहत छोटे-छोटे गांव में संपत्ति महिलाओं के नाम होने लगी है। आज देश के 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश कराया है। जिन परिवारों को पक्का घर मिला है या घर मिलना पक्का हुआ, उनके जीवन की नई शुरुआत है। पीएम ने कहा कि मैं एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश में गया था। उस परिवार को भी पीएम आवास मिला है। आदिवासी बहन ने मुझे खीर खिलाई। जब मैं खीर खा रहा था तो मुझे मां की याद आई। आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। यह मेरे जीवन की पूंजी है।

वंचितों, गरीब, गांव, दलित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा बदलाव मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। पिछले 10 वर्ष में केवल केंद्र में रहते हुए हमने साबित किया कि ओडिशा हमारी प्राथमिकता है। अब ओडिशा को 10 साल के मुकाबले तीन गुना ज्यादा बजट मिल रहा है।

ओडिशा में केंद्र की योजनाओं को लागू किया गया है। 70 साल के ऊपर के वृद्ध को आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिलेगा। आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। आदिवासी युवाओं को शिक्षा, रोजगार, ओडिशा की महिला को देश की माननीय राष्ट्रपति बनाने जैसे काम हमने किए हैं।

ओडिशा के कई इलाके विकास से वंचित थे। जनजातियों के विकास के लिए पीएम जन मन योजना शुरू की गई है। ओडिशा की 13 जनजातियों को योजना का लाभ मिल रहा है। देश पारंपरिक कौशल पर फोकस कर रहा है। 18 पेशों को विश्वकर्मा योजना से जोड़ा। इस पर 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। लाभार्थियों को ट्रेनिंग, ऋण मुहैया करा रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

चेन्नई में तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है भारत

चेन्नई। बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच स्पिनर्स के लिए हमेशा से मददगार होती है। ऐसे में पहले मुकाबले में टीम इंडिया तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है।

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 19 सितंबर से खेला जाएगा। सूत्रों के अनुसार, चेन्नई में लाल मिट्टी की पिच का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में पिच में उछाल और तेजी भी देखने को मिल सकती है। यहां की उमस भरी गर्मी को ध्यान रखते हुए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर तीन स्पिनर्स को मौका दे सकते हैं।

पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 में दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय माना जा रहा है। वहीं, तेज गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के चुने जाने की संभावना है। तीसरे स्पिनर की दौड़ में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आकाश दीप और यश दयाल शामिल हैं। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप और ऑलराउंडर अक्षर पटेल के बीच टीम में जगह बनाने की जंग है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, कप्तान कुलदीप पर भरोसा जता सकते हैं। इस स्थिति में में पिछले कुछ समय से अपने ऑलराउंड खेल से लगातार प्रभावित करने वाले अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ सकता है।

लाल मिट्टी की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। वहीं, चेपॉक की पिच हमेशा से स्पिनर्स के मुफीद रही है। 2021 में भारत ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले चेन्नई में खेले थे। मेहमानों ने पहला मुकाबला 227 रन से जीता था जबकि दूसरा मैच भारत ने 317 से अपने नाम किया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 83,079 के ऑलटाइम हाई पर

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 91 अंक मजबूत होकर 83,079.66 के नए ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी का रुझान जारी रहा। यह 35 अंक की बढ़त लेकर 25,418.55 के नए शिखर पर पहुंच गया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 90.88 अंक या 0.11 प्रतिशत की बढ़त लेकर 83,079.66 के नए ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 82,866.68 और 83,152.41 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 34.80 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 25,418.55 के नए शिखर पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 25,352.25 और 25,441.65 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

थोक महंगाई दर चार महीने में पहली बार दो फीसदी के नीचे

नई दिल्ली। थोक मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई के 2.04 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में घटकर 1.31 प्रतिशत रह गई। सरकार ने मंगलवार को इसके आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार कमोडिटी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण थोक मुद्रास्फीति चार महीनों में पहली बार 2 प्रतिशत से नीचे आ गई। 17 सितम्बर को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मुद्रास्फीति अगस्त माह में घटकर 1.31 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले महीने यह 2.04 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों, दालों और अनाजों में स्थिर मुद्रास्फीति और सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति में वृद्धि ने उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के इजाफे में योगदान दिया। अगर कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तरों पर बनी रहीं तो थोक मुद्रास्फीति में और गिरावट आने की संभावना है।

अवाडा समूह ने दिया मप्र में रू. 5,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

भोपाल। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में काम करने वाले अवाडा समूह ने मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। समूह के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वन टु वन बातचीत के दौरान दिया। अवाडा समूह सौर मॉड्यूल, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और हरित हाइड्रोजन, हरित मेथनॉल, हरित अमोनिया तथा टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के विकास का काम करता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव गांधीनगर में तीन दिवसीय रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने गांधी नगर गए थे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विंड पॉवर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में सोलर पार्क के तर्ज पर विंड पार्क भी विकसित किए जाएं। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान टॉरेंट पॉवर ने प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के लिए नीति तैयार करने का अनुरोध किया।

केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन 25 सितंबर को लाएगी आईपीओ

नईदिल्ली। केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड 25 सितंबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाएगी। इसका मकसद कंपनी की विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाना है। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार, आईपीओ 27 सितंबर को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 24 सितंबर को बोली लगा पाएंगे। राजस्थान स्थित यह कंपनी 'हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग' और 'रेफ्रिजरेशन' (प्रशीतन) उद्योग के लिए फिन और ट्यूब प्रकार के 'हीट एक्सचेंजर्स' बनाती है। दस्तावेजों के अनुसार, आईपीओ में 1.55 करोड़ के ताजा शेयर शामिल है। इसमें कोई बिक्री पेशकश शामिल नहीं है। कंपनी ने आईपीओ पूर्व प्लानिंग साइकल में 9.54 करोड़ रुपये जुटाने की पिछले महीने घोषणा की थी।

दरों में कटौती और शेयरों के भाव

देवाशिष बसु

दुनिया भर के निवेशक शेयर बाजारों में उछाल का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जल्द ही कटौती के संकेत दिए हैं, जिनसे उनके भीतर उत्साह भर गया है। पारंपरिक मान्यता तो यही है कि फेड दरों में कटौती करता है तो शेयरों के भाव चढ़ने लगते हैं। इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि इस सप्ताह फेड की बैठक में दरों में 50 आधार अंक तक की कटौती हो जाएगी।

ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है और अब वह फेड के 2 फीसदी के लक्ष्य के आसपास है। क्या दरों में कटौती से शेयरों के भाव चढ़ेंगे? यह निराश करने वाली बात है कि आंकड़ों के मुताबिक ब्याज दरों में चाहे इजाफा हो या कटौती, शेयर बाजार का प्रदर्शन उससे बहुत अधिक नहीं जुड़ा होता। एसऐंडपी 500 जैसे व्यापक सूचकांकों को देखकर तो यही लगता है। दरों में इजाफे के ताजा उदाहरण से इसकी शुरुआत करते हैं-

वर्ष 2022 में फरवरी के मध्य में मैंने इस स्तंभ में अटकल लगाई थी कि अगर फेड मुद्रास्फीति से मुकाबला करने के लिए दरों में इजाफा करता है तो क्या वास्तव में बाजार में तेजी आएगी? यह परिकल्पना उस पारंपरिक मान्यता के विपरीत थी, जिसमें माना जाता था कि दरों में इजाफे के दौरान बाजार गिरते हैं और दरों में कटौती के दौरान उनमें इजाफा होता है। मेरा नजरिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित था।

उदाहरण के लिए 2004 के मध्य से 2006 के मध्य तक फेड ने 17 बार दरों में इजाफा किया मगर एसऐंडपी 500 में 46 फीसदी तेजी आई। इसी प्रकार दिसंबर 2015 से दिसंबर 2020 के बीच फेड ने दरों में नौ

बार इजाफा किया जो 0.25 फीसदी से लेकर 2.5 फीसदी तक था। इस दौरान एसऐंडपी 1,900 से 2,800 पर पहुंच गया। दिलचस्प है कि 2018 में जब सूचकांक डगमगाया तब दरों में इजाफे का तीन साल का चक्र खत्म हो रहा था, शुरू नहीं।

वर्ष 2022 में क्या हुआ? फेड द्वारा दरों में इजाफे और यूक्रेन युद्ध के बीच बाजार में कुछ महीने के लिए गिरावट अवश्य आई। इसके बावजूद पारंपरिक समझ को धता बताते हुए बाजारों ने तेजी से वापसी की और फेड के इच्छित ब्याज दर इजाफे के एक तिहाई तक पहुंचते-पहुंचते इनमें इजाफा हो गया। एसऐंडपी 500 अक्टूबर 2022 में 3,500 तक गिर गया। उसके बाद इसने वापसी की और जुलाई 2023 तक यह 4,600 पर पहुंच गया। इस दौरान फेड ने दरों में छह बार इजाफा किया और यह नवंबर 2022 के 3.25 फीसदी से बढ़कर जुलाई 2023 में 5.5 फीसदी हो गई।

दिलचस्प है कि फेड ने जुलाई में दरें बढ़ाना रोका और अक्टूबर तक एसऐंडपी 500 में गिरावट आई। अक्टूबर के बाद से सूचकांक चढ़ता गया और पिछले सप्ताह की गिरावट के पहले वह बढ़कर 5,650 तक पहुंच गया। इस पूरी अवधि में अर्थव्यवस्था 5.5 फीसदी पर ही रुकी रही। एक पूरे चक्र में दरों में 0.25 फीसदी से 5.5 फीसदी इजाफा हुआ और एक वर्ष तक यह स्तर बरकरार रहा। इसके बावजूद बाजार में लगातार तेजी बनी रही। यह फेड के रुख से अलग था। यह पहला मौका नहीं है जब फेड द्वारा दरों में बदलाव तथा शेयर बाजार की हलचल के बीच का संबंध अलग निकला हो। इसके विपरीत परिदृश्य पर विचार करें तो क्या फेड द्वारा दरों में कटौती के समय बाजार में तेजी आती है? यहां भी रिश्ता कमजोर नजर आता है। सबसे चकित करने वाला उदाहरण 2008 का है। जनवरी 2008 में बाजार में गिरावट के बाद फेड ने दरों में कटौती की और उन्हें 3.5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया। मार्च में बियर स्टर्न के पतन के बाद 0.75 फीसदी कटौती हुई और यह 2.25 फीसदी रह गई। अप्रैल में दरों में और कमी करके इन्हें दो फीसदी कर दिया गया और जून से सितंबर के बीच बाजार और गिरे। सितंबर में ही लीमन ब्रदर्स का भी पतन हुआ। अक्टूबर तक दरें घटकर 1.5 फीसदी रह गईं और फिर 1 फीसदी। दिसंबर तक यह घटकर शून्य से 0.25 फीसदी रह गई।

सभी जिलों में खुलेंगे अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रः साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र और पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस मौके पर श्रमिकों को विश्वकर्मा दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 57 हजार से अधिक पंजीकृत परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 49.43 करोड़ रूपए की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में श्रमवीरों को शाल और प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक 'क्रेडल्स ऑफ होप' का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की। मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों के हित में श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए श्रमेव जयते एप और श्रमिक हेल्पलाइन नंबर की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने ढाई से 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम किया। तब श्रमिकों को बहुत ही कम पेंशन राशि मिलती थी। प्रधानमंत्री की पहल पर यह राशि बढ़ाकर एक हजार रूपए की गई। साथ ही प्रोविडेंट फंड बनाकर श्रमिकों को यूनिवर्सल नंबर आबंटित किए गए। इस यूनिवर्सल नंबर के जरिए श्रमिकों को देश के किसी भी स्थान जाने पर इस स्थायी नंबर के जरिए विभिन्न लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार श्रमिक भाई पीएफ की राशि क्लेम नहीं करते थे, उन्हें 27 हजार करोड़ रूपए दावा राशि का भुगतान कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

श्रमिकों को आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। श्रमिकों के बीच अब कोई बिचौलिया नहीं आएगा। श्रमिकों को अब राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाएं जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री श्री साय उन योजनाओं को पुनः शुरूआत कर रहे हैं। यह श्रमिकों के लिए खुशी का अवसर है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 235 करोड़ रूपए अलग-अलग योजना के माध्यम से सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की गई है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रमेव जयते एप और शिकायत निवारण पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अब श्रमवीरों द्वारा किसी भी समय अपने शंका, समस्या का निवारण घर बैठे कर सकते हैं। रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्रमवीर हमारे प्रदेश के रीड़ की हड्डी है, इनके दम पर ही हमारा राज्य प्रगतिशील है। श्रमवीरों के सच्चे सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि श्रमवीरों के बच्चों के भविष्य व शिक्षा के लिए हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरू खुशवंत साहेब, श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलेरमंगई डी., इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त श्रीमती सविता मिश्रा एवं एल.ए. जांगड़े सहित बड़ी संख्या श्रमवीर, विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा का सेवा पखवाडा का शुभारंभ

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम तेलीबांधा तालाब में मुख्यमंत्री जी द्वारा सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया तत्पश्चात सभी मंडलों में अलग-अलग स्थानों पर अनेक सेवा कार्य जिलाध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में किया गया।

सेवा पखवाडा कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष गोपी साहू ने बताया की प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बिरगांव मंडल द्वारा सरोरा में सफाई अभियान, वृक्षारोपण एवं सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा महामाया मंदिर वार्ड में तालाब की सफाई की गई एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जयस्तंभ चौक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा कुष्ठ बस्ती पंडरी में फल वितरण का कार्य किया गया साथ ही महिला मोर्चा द्वारा भी वृद्धा आश्रम श्याम नगर में भी फल वितरण का सेवा कार्य किया। जवाहर नगर मंडल के अंतर्गत शारदा चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर सफाई कर पुष्पांजलि अर्पित गिया गया साथ ही फल वितरण किया गया। एवं किसान मोर्चा द्वारा हिरापुर में 80 किसानों का श्रीफल और साल से सम्मानित किया गया। आज उक्त कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, प्रदेश महामंत्री किशोर महानंद, जिला महामंत्री सत्यम दुवा, गोपी साहू, अकबर अली, शैलेंद्री परगनिया, ओमप्रकाश साहू, राजकुमार राठी, तोषण साहू, गौरी शंकर श्रीवास, अन्जय शुक्ला, मखमूर खान, मिर्जा एजाज बेग, मोर्चा अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता, सीमा साहू, गज्जू साहू, सुनील चौधरी, यादराम साहू, अखिलेश कश्यप, अनुराग पांडे, रामेश्वर पटेल, रामलाल साहू, नसीर खान, मंडल अध्यक्ष संतोष साहू, गोरेलाल नायक, रविन्द्र ठाकुर, पार्षद सुनील चंद्राकर, प्रमोद साहू, रोहित साहू, मृतुन्जय दुबे, कमलेश बसंत वर्मा, नवीन सिंह, मुकेश साहू, योगेश साहू, अर्पित सूर्यवंशी, प्रणय साहू, स्वपनिल मिश्रा, मिली बैनर्जी, अर्चना हुकरे, रमेश शर्मा, योगेश साहू, मुकेश शर्मा, ललित बुंदेला, घनश्याम रक्सेल, नरेन्द्र यादव सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सेवा पखवाडा में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पांव पखारकर जनसेवा का दिया अद्वितीय उदाहरण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन का एक भावुक और अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसेवा की नई मिसाल कायम करते हुए हितग्राहियों के पांव पखारकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को यह संदेश भी दिया है.

भ्रष्टाचार करने स्कूली किताबों को रद्दी में बेची गई

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि दो दिन एक बड़ा सनसनी क्षेत्र खुलासा करते हुए सरकार की लापरवाही को उजागर किया गया। रियल बोर्ड पेपर मिल, सिलियारी सिलयारी में एक पेपर मिल के गोदाम में भारी मात्रा में स्कूली किताबों का जखीरा मिला। इस मामले में पतासाजी करने पर पता चला कि यह किताबें रद्दी में बेची गयी हैं।

रायपुर के सिलियारी स्थित रियल पेपर मिल में लाखों किताबें कबाड़ में फेंकी जा रही हैं। ये वही किताबें हैं, जो सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त वितरण के लिए छपवाई गई थीं। सरकार ने किताबें छपवाई, लेकिन उन्हें छात्रों तक पहुंचाने के बजाय कबाड़ में बेच दिया। यह शिक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ भारी भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। यह किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित की गई थीं, जो छात्रों को निशुल्क दी जानी थीं। इस पूरे मामले में एक बड़े भ्रष्टाचार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। एक ओर पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी ओर बिना बांटे किताबों को रद्दी में किलो के भाव बेचे जाने का यह मामला बताता है कि किताबें छापने और बांटने का भ्रष्टाचार का खेल कैसा चल रहा है। किताबें जितनी मात्रा में छपनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में छापा गया और फिर एजेंसी द्वारा छापने की राशि सरकार से ले ली गई, फिर उन्हीं किताबों को रद्दी में बेच दिया जाता है। सीधे-सीधे करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है और जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग इस प्रकरण में संलिप्त नहीं रहेंगे तब तक ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा इस पूरे प्रकरण के खानापूर्ति के लिए पाँच सदस्यीय जाँचदल का गठन किया जाता है जिसमें से दो लोग पूर्व से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, हम इस जाँचदल की बजाय सीबीआई जाँच या फिर रिटायर्ड जज की अगुवाई में इस प्रकरण के जाँच की माँग करते हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। सवाल यह है: कि कबाड़ में फेंकी जा रही इन किताबों का जिम्मेदार कौन है? यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रकरण को सदन में उठाए जाने की बात कहते हुए बच्चों के भविष्य को कबाड़ में डालने वाली सरकार से श्वेत पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है। आज के इस प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा, पूर्व विधायक अनिता शर्मा जी एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष उधोराम वर्मा जी शामिल हुवे।

तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत

रायपुर। रायपुर में तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों नहाये गए हुए थे। इस दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अपना गार्ड तालाब का है। जानकारी के अनुसार, दोनों मासूम नहाये गए हुए थे। इसमें से एक बच्चे का उम्र आठ साल और एक का उम्र दस साल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों बच्चे के यूनिफॉर्म और जूता तालाब के बाहर मिले। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई है।

रेलवे टिकट का दलाली करने वाला गिरफ्तार

रायपुर। रेलवे सुरक्षा बल ने मंदिर हसौद इलाके के चंद्रखुरी में पर्सनल यूजर आईडी से ट्रेनों का आरक्षित टिकट बनाकर बेचते हुए अश्वनी वर्मा (28) को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 36 हजार रुपये कीमत का 39 ई टिकट बरामद किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक एसके राठौर ने बताया कि नरदहा रोड चंद्रखुरी स्थित डिजिटल सेवा सर्विस पाइंट की आड़ में अश्वनी वर्मा कई दिनों से रेलवे का आरक्षित ई-टिकट बनाकर बेचता आ रहा था।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

पितृ पक्ष पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का महापर्व

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, पितृ पक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। डॉ. महंत ने कहा कि, शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में पितृगण अपने परिजनों के समीप विविध रूपों में आते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। परिजनों से संतुष्ट होने पर पूर्वज आशीर्वाद देकर हमें अनिष्ट घटनाओं से बचाते हैं। श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वालों को सुख-समृद्धि, सफलता, आरोग्य और संतान रूपी फल देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मवैवर्तपुराण में यह निर्देश है कि इस संसार में आकर जो सद्गृहस्थ अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान, तिलांजलि और ब्राह्मणों को भोजन कराते है, उनको इस जीवन में सभी सांसारिक सुख और भोग प्राप्त होते हैं। वे उच्च शुद्ध कर्मों के कारण अपनी आत्मा के भीतर एक तेज और प्रकाश से आलोकित होते है। मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध करने वाले सदगृहस्थ को स्वर्गलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।

आपदा पीड़ितों के लिए 298 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य में सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अग्नि, दुर्घटना, ओलावृष्टि, आधी-तूफान आदि के मामलों में अब तक 298.66 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य के सभी कलेक्टरों को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय मंत्रालय में स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी संकलित कर पीड़ितों को प्रदाय की जा रही इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 298 करोड़ 66 लाख 55 हज़ार रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता राशि सभी 33 जिलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए का प्रावधान के साथ-साथ निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

रायगढ़ जिले में 900 से अधिक शहरी परिवारों को मिली खुशियों की चॉबी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रांसफर की। 'मोर आवास-मोर अधिकार' कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ शहरी क्षेत्र के 900 से अधिक हितग्राहियों को पांव पखार कर गृह प्रवेश के लिए चॉबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल रूप से जुड़कर आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की हैं। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

महादेव सट्टा ऐप मामले के 10 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों को आज रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। इन आरोपियों का चालान पेश हो चुका था और उन्हें आरोप पूर्व तर्क के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि, कोर्ट में एक वकील के निधन के कारण मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है। इन 10 आरोपियों में से एक आरोपी चंदभूषण वर्मा की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि वर्तमान में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 14 आरोपी रायपुर जेल में बंद हैं। मंगलवार को इनमें से जेल में बंद 10 आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया था। जिन आरोपियों की पेशी हुई उनमे रितेश कुमार यादव, राहुल वक्टे, चंद्र भूषण वर्मा, सतीश चंद्राकार, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, अमित कुमार अग्रवाल, अर्जुन सिंह यादव, नीतीश दीवान, और किशन लाल वर्मा शामिल हैं। मामले की आगामी सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

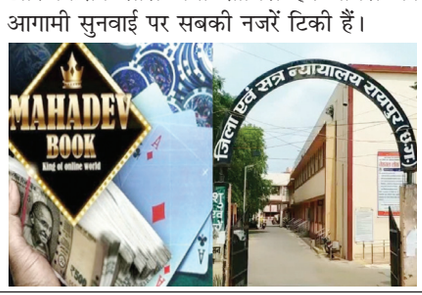

कांग्रेस नेता ने कोर्ट में किया सरेंडर

रायपुर। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. उनके खिलाफ सरकंडा, सिविल लाइन और सकरी थाने में मामला दर्ज है. बता दें कि जमीन को जबरदस्ती बेचने मृतक सिद्धान्त नागवंशी पर दबाव बनाया जा रहा था. इसके चलते तंग आकर युवक ने खुदकुशी की है. परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता तैय्यब हुसैन के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था. जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता तैय्यब हुसैन और अकबर खान ने सकरी निवासी सिद्धांत नागवंशी और चांटीडीह निवासी रज्जब को इतना प्रताड़ित किया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली.चांटीडीह में रहने वाले कांग्रेस नेता रज्जब अली ने चार अक्टूबर 2022 को अपने घर के पास पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें अकबर और तैय्यब के प्रताड़ना से आत्महत्या करने की बात लिखी थी. घटना के बाद उसके बेटे अरमान उर्फ हमाम अली ने पूर्व पार्षद तैय्यब हुसैन और अकबर खान पर जमीन के मामले में प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जनवरी 2024 में दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया. इसी तरह सकरी थाना क्षेत्र के सिद्धांत नागवंशी ने भी आत्महत्या की थी.

पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा सांसद अग्रवाल ने की

मोदी सरकार के 100 दिन ने हुए रिकॉर्ड स्तर के कार्यः अग्रवाल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता सम्हालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि इन प्रथम 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू करके भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य-पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी-सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। भाजपा सांसद श्री अग्रवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रु. के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसी प्रकार लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी दी गई। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएंगी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 की चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि इस योजना में 49,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण व अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए कार्य स्वीकृत हुआ। 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भाजपा सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि किसान मित्र मोदी योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं। 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया जिससे 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रु. का लाभ हुआ। 12,100 करोड़ रु. की लागत से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। 14,200 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी मिली जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल है। इससे कृषि क्षेत्र में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मसौदा नीति भी तैयार कर ली गई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड व जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच एमओयू करके उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा और लाभ का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 से घटाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय भी लिया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.